

गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब के सेवन से अब तक 6 की मौत, 21 अस्पताल में भर्ती

भावनगर,एजेंसी। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद भावनगर शहर और ग्रामीण इलाकों में कथित तौर पर जहरीली शराब के सेवन से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 21 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में उपचाराधीन हैं। बीती रात में पांच लोगों की मौत हो चुकी थी। आज सुबह एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए गुह विभाग ने जांच स्टेट मॉनिटरिंग सेल (एसएमसी) को सौंप दी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपितों ने कथित तौर पर ब्रांडेड रॉयल स्टैंग शराब की खाली बोतलें, ढक्कन और स्टिकर जुटाए और उनमें केमिकल मिश्रित जहरीला तरल भरकर नकली शराब के रूप में बेच दिया। एफएसएल और मेडिकल जांच के अनुसार, जहरीली शराब की चपेट में आए 10 मरीजों के रक्त और यूरिन सैंपल में करीब 38.59 प्रतिशत घातक मेथनॉल पाया गया, जबकि इथेनॉल की मात्रा केवल 0.94 प्रतिशत बताई गई है।

पुलिसकर्मों की पार्टी से सामने आया मामला :मामले की कड़ी पुलिस कर्मों की एक पार्टी के बाद सामने आई। 18 अगस्त को भावनगर जिले के पुलिस थानों को एलसीबी की ओर से सतर्क किया गया था। खरकड़ी गांव के रहने वाले विजयराजसिंह गोहिल का पुलिस भर्ती में चयन होने पर उन्होंने अपने दोस्तों उपेन्द्रसिंह गंभीरसिंह गोहिल, हरपालसिंह रॉयल स्टैंग शराब पी थी। इनमें से उपेन्द्रसिंह गोहिल को पार्टी दी थी। जयदीपसिंह को छोड़कर अन्य तीन दोस्तों ने कथित तौर पर रॉयल स्टैंग शराब पी थी। इनमें से उपेन्द्रसिंह गोहिल की 18 अगस्त को मौत हो गई।

अहमदाबाद से मंगाया गया केमिकल, उज्जैन से बुलाया गया ‘डॉक्टर’ जांच के मुताबिक, यह पूरा नेटवर्क आर्थिक लाभ के लिए कथित रूप से एक सिंडिकेट के रूप में चलाया जा रहा था। वरतेज के नया प्लॉट इलाके की आंबलीवाली शेरी में रहने वाले कथित बुकी/बूटलेगर गोतम सोलंकी और रईस के बीच भावनगर में नकली शराब तैयार करने की डील हुई थी।

बताया गया है कि अहमदाबाद के सरखेज इलाके से सफेद तरल पदार्थ, खाली बोतलें, ढक्कन, स्टिकर और मेथनॉल मंगाया गया। केमिकल का मिश्रण तैयार करने के लिए उज्जैन से नरेंद्रसिंह उर्फ ‘डॉक्टर’ को बुलाया गया था।

पुलिस के अनुसार केमिकल मिश्रण तैयार करने वाले नरेंद्रसिंह ने खुद भी कथित तौर पर यही जहरीला तरल पी लिया था। उसकी तबीयत 17 अगस्त को बिगड़ी और 18 अगस्त को उसकी मौत हो गई।

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का तिहाड़ में निधन

सिख विरोधी दंगों में उग्रकैद काट रहे थे; 3 केस में से एक में बरी, 2 में दोषी थे



नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व सांसद और नेता सज्जन कुमार का गुजरात को 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक, सज्जन कुमार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था। वह 1984 के सिख विरोधी दंगों के तीन में दो मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में उग्रकैद की सजा काट रहे थे। उन्हें एक केस में बरी कर दिया गया था।

सज्जन कुमार- 1980 में पहली बार दिल्ली के सांसद बने सज्जन कुमार का जन्म 23 सितंबर 1945 को दिल्ली में हुआ था। वे मैट्रिक तक पढ़े थे। उनकी राम कौर से शादी हुई थी। उनके एक बेटा और दो बेटियां हैं। उन्होंने 1977 में दिल्ली नगर निगम पार्षद के तौर पर राजनीति शुरू की।

बाद में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बने। 1980 में पहली बार बाहरी दिल्ली से सांसद चुने गए। 1991 और 2004 में भी इसी सीट से सांसद रहे। संसद में उन्होंने शहरी विकास और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से जुड़ी समितियों में काम किया।1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों ने सज्जन कुमार के राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया।

ऑक्टरों को एक यूनिक आईडी मिलेगी

नेशनल मेडिकल कमीशन का प्रस्ताव



नई दिल्ली,एजेंसी। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने हर रिजस्टर्ड डॉक्टर को केन्द्रीय स्तर पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UID) देने का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद एक बार राज्य मेडिकल रिजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होने पर डॉक्टर को देश के किसी दूसरे राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए अलग से नया रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लेना होगा।

प्रस्ताव के तहत डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस की स्थिति और डॉक्टर के खिलाफ हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी दर्ज रहेगी। यह रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिसे मरीज और अस्पताल भी देख सकेंगे।

लिंग निर्धारण अपराध में पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती

सुप्रीम कोर्ट बोला:अस्पताल पर छापा मारने का अधिकार भी नहीं, अब स्पेशल टीम करेगी कार्रवाई

जांच भी नहीं कर सकती पुलिस

बेंच ने कहा कि प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, 1994 से जुड़े मामलों में मेडिकल जानकारी और संवेदनशीलता की जरूरत हो सकती है।

कोर्ट ने कहा कि PCPNDT कानून के तहत होने वाले अपराधों के लिए पुलिस मुख्य जांच अधिकारी नहीं है।

पुलिस सीधे तौर पर न तो FIR कर सकती है और न ही डॉक्टरों या अस्पतालों के खिलाफ एक्शन ले सकती है।

पुलिस सिर्फ तभी कार्रवाई कर सकती है, जब उपयुक्त प्राधिकारी उनसे मदद मांगे।

‘वैवाहिक विवाद में कराया जा सकता है बच्चे का पैटरनिटी टेस्ट’, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

नई दिल्ली,एजेंसी। शादी के दौरान पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वैवाहिक विवाद में बच्चे का पैटरनिटी टेस्ट कराया जा सकता है। यह मामला तब सामने आया जब एक पति ने अपनी पत्नी के कथित अनेतिक चरित्र के आधार पर तलाक मांगा और दावा किया कि वह बच्चे का बायोलॉजिकल पिता नहीं है।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने उस महिला की याचिका खारिज कर दी जिसने बच्चे के पैटरनिटी टेस्ट का विरोध किया था। महिला का तर्क था कि कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्ष को DNA टेस्ट कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, और उसके पति की तलाक की याचिका का फैसला पैटरनिटी टेस्ट के बिना ही किया जाना चाहिए।

शाह बोले: कांग्रेस का पूरा वंदे मातरम न गाना देशविरोधी

उन्होंने 1937 में राष्ट्रगीत के दो टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया और विभाजन की नींव डाली

शाह ने कहा- कांग्रेस संसद के कानून को नहीं मान रही

अमित शाह ने कहा, ‘कांग्रेस का सिर्फ दो पैरा वंदे मातरम गाने का फैसला तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति है। देश में अब तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी।’ 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया था। आज कांग्रेस उसी पुराने फैसले को फिर लागू कर रही है। ‘देश की जनता को कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। BJP इसका जनता के बीच और विधानसभा में भी जोरदार विरोध करेगी।’

था। यह हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है। BJP स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं थी। उनके लिए यह राजनीतिक मुद्दा है। दरअसल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बुधवार को ऐलान किया कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 पैरा में से सिर्फ शुरुआती दो पैरा गाएगी। यह फैसला 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को लेकर हुए विवाद के बाद आया।

खरगे ने पीएम केयर्स फंड को लेकर सार्वजनिक जवाबदेही की मांग की

अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग बोला: आरएसएस पर बैन लगे यहाँ आने वाले संघ के नेताओं को सम्मान न मिले; भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क जाएंगे

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम केयर्स फंड को लेकर सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट के हवाले से कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में पीएम केयर्स फंड में 8,452 करोड़ रुपये की राशि थी, जबकि इस दौरान महज 87.85 लाख रुपये खर्च किए गए, जो फंड की समाप्ति शेष राशि का करीब 0.01 प्रतिशत है। खरगे ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा प्रधानमंत्री के नाम वाले इस फंड को सार्वजनिक निगरानी की सामान्य व्यवस्थाओं से बाहर क्यों रखा गया है। आपातकालीन फंड में हजारों करोड़ रुपये जमा रहने और एक साल में उसीकी शेष राशि का महज 0.01 प्रतिशत खर्च होने का असह्य वया है। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के अध्यक्ष हैं, जबकि रक्षा, गुह और वित्त मंत्री इसके न्यासी हैं। फंड को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत योगदान और कर कटौती योग्य दान भी प्राप्त होते हैं। इसके बावजूद इसे सूचना का अधिकार, निर्यंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच और संसद के स्तर पर जवाबदेही से बाहर क्यों रखा गया। खरगे ने प्रधानमंत्री से दो सवाल किए। पहला, प्रधानमंत्री के नाम वाले फंड को सार्वजनिक जांच-पड़ताल की सामान्य व्यवस्थाओं से बाहर रखने का कारण क्या है? दूसरा, जब 2024-25 में फंड की समाप्ति शेष राशि का महज 0.01 प्रतिशत खर्च हुआ, तो हजारों करोड़ जमा रखने वाले आपातकालीन फंड का औचित्य क्या है? खरगे ने कहा कि उन्हें पीएम केयर्स फंड और उससे जुड़ी सार्वजनिक जवाबदेही के सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने फंड की राशि, उसके उपयोग और निगरानी की व्यवस्था को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।

उल्लेखनीय है कि पीएम केयर्स फंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी 2024-25 के ऑडिटेड खातों के मुताबिक, जब 2020 में महज 2.25 लाख रुपये से शुरू हुए इस फंड में 31 मार्च 2025 तक 8,452 करोड़ रुपये जमा हो चुके थे। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में फंड को देश के भीतर से 479.04 करोड़ रुपये और विदेशों से करीब 92 लाख रुपये का दान मिला।

वाशिंगटन,एजेंसी। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF ने RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने अमेरिकी सरकार से RSS नेताओं को राजनयिक सम्मान नहीं देने और उनके साथ उच्चस्तरीय बैठकें नहीं करने को कहा है।

आयोग के चेयरमैन आसिफ महमूद ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RSS के सदस्य हैं और इसके सहयोगी संगठनों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं।

पाकिस्तानी मूल के महमूद का यह बयान RSS प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे से कुछ दिन पहले आया है। भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे।

100 से ज्यादा संगठनों ने भागवत के कनाडा दौरे का समर्थन किया

कनाडा के 100 से ज्यादा संगठनों ने क्रस्-प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित दौरे का समर्थन किया है। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और मंत्रियों को पत्र लिखकर भागवत को रोकने की मांगों को खारिज करने की अपील की। संगठनों ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले पुष्टि और स्वतंत्र सबूत होने चाहिए और कानून के मुताबिक पूरी प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

भागवत 29 अगस्त को अमेरिका गए थे और शिकागो में न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदू फॉर एगोज़मेट एंड डायलॉग (AHEAD) के ‘यूनियर्सल ऑननेस सॉलिब्रेशंस’ कार्यक्रम में शामिल होंगे। भागवत सितंबर 2018 में जिक्र नहीं मिला।



ब्रिटिशकालीन नवशों का होगा अध्ययन

बैठक का सबसे अहम मुद्दा भारत-नेपाल के बीच चल रहे सीमा विवाद का समाधान रहेगा। इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया के पुराने रिकॉर्ड और ब्रिटिश शासनकालीन नक्शों का अध्ययन किया जाएगा। दोनों देशों के अधिकारी इन दस्तावेजों का मौजूदा भौगोलिक स्थिति से मिलान कर विवादित सीमा क्षेत्रों पर एक राय बनाने की कोशिश करेंगे। सीमा पर जमीन और सीमा निर्धारण से जुड़े मामलों में पुराने अभिलेखों की भूमिका अहम मानी जा रही है। अधिकारी ब्रिटिशकालीन नक्शों के साथ उपलब्ध अन्य दस्तावेजों और वर्तमान स्थिति का अध्ययन करेंगे।

दिल्ली दवा खरीद घोटाला: 650 करोड़ के मामले में अहम फाइलें नष्ट करने का आरोप,

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार की केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) में दवा और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में हुए 650 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच में महत्वपूर्ण फाइलों को नष्ट किए जाने का आरोप सामने आया है। एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने कोर्ट में जानकारी दी है। कोर्ट में कहा, पहले गायब बताई जा रही घोटाले से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलों को जानबूझकर नष्ट किया गया। इन फाइलों में टेंडर, खरीद की दर, आपूर्ति, स्टॉक और अधिकारियों की भूमिका से जुड़ी अहम जानकारी होने की संभावना थी। बताया कि पहले जिन 7 फाइलों के गायब होने की बात सामने आई थी, उनमें से प्रत्येक घोटाले की अलग कड़ी खोल सकती थी। फाइलें मिलती तो खरीद की प्रक्रिया से लेकर अस्पतालों तक आपूर्ति और भुगतान की स्थिति का मिलान किया जा सकता था।

सात फाइलों में छिपी थी घोटाले की कड़ी: करीब 16.67 लाख वस्तुओं की खरीद और करीब 75 करोड़ रुपये के खर्च का ब्योरा। इससे अस्पतालवार आपूर्ति,



स्टॉक और वास्तविक खपत का पता चलता। करीब 50 लाख सैशे की खरीद पर करीब 7.50 करोड़ रुपये खर्च का रिकार्ड। इससे पता चलता कि कितने सैशे किस अस्पताल को भेजे गए और कितना स्टॉक बचा। 448 मशीनों की खरीद, कीमत, आपूर्ति, स्थापना और अस्पतालवार आवंटन का ब्योरा। इससे यह जांची जा सकती थी कि खरीदी गई सभी मशीनें वास्तव में अस्पतालों में पहुंचीं और स्थापित हुई या नहीं। सात सी-आर्म मशीनों

की करीब 7.70 करोड़ रुपये की खरीद का रिकार्ड। इससे खरीदी गई मशीनों के प्राप्तकर्ता अस्पताल और उनकी वर्तमान स्थिति का पता चलता। खरीद, निरीक्षण, आपूर्ति और अस्पतालों में स्थापना से संबंधित विवरण। इससे यह पता चलता कि कितने उपकरण खरीदे गए और वास्तव में कितने अस्पतालों में लगाए गए। 100 करोड़ रुपये से अधिक की सर्जिकल सामग्री की खरीद का ब्योरा। इसमें

ड्रेसिंग सामग्री, टांके, कैनुला और दस्ताने जैसी सामग्री शामिल थी। इससे खरीद की मात्रा, दर और अस्पतालवार आपूर्ति का मिलान किया जा सकता था। करीब 400 करोड़ रुपये की दवाओं की खरीद का

रिकार्ड। इससे दवाओं की मात्रा, संबंधित कंपनियां, अस्पतालों को आपूर्ति और स्टॉक रजिस्टर का मिलान कर यह पता लगाया जा सकता था कि खरीदी गई दवाएं वास्तव में कहाँ गईं।

448 एक्स-रे मशीनों पर 148 करोड़ खर्च

जांच में पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों की खरीद पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि करीब 10 लाख रुपये की मशीन करीब 33 लाख रुपये प्रति मशीन की दर से खरीदी गई। 448 मशीनों पर करीब 148 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि इनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 45 करोड़ रुपये बताई गई है। ब्रेडशीट करीब 150 रुपये के बजाय 450 रुपये में खरीदने का आरोप है। इस मद में करीब 75 करोड़ रुपये खर्च किए गए। सी-आर्म करीब 25 लाख रुपये के बजाय 1.10 करोड़ रुपये प्रति मशीन की दर से खरीदे जाने का आरोप है। ओआरएस करीब 2.05 रुपये के बजाय 15 रुपये प्रति सैशे की दर से खरीदने का आरोप है। 118 मई 2026 को जांच टीम सीपीए से रिकार्ड लेने पहुंची थी। उस समय महत्वपूर्ण फाइलें उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। अब एसीबी की ओर से कोर्ट में इन्हें नष्ट किए जाने की बात कहे जाने से मामले में साक्ष्य मिटाने का पहलू भी जुड़ गया है। वहीं, ई-टेंडर, भुगतान, लेखा और स्टॉक से जुड़े डिजिटल रिकार्ड के जरिये इन फाइलों में दर्ज कई जानकारियां दोबारा जुटाई जा सकती हैं। इनसे टेंडर तैयार करने से लेकर खरीद की मंजूरी, आपूर्ति और भुगतान पाने वाली कंपनियों तक की पूरी कड़ी जोड़ने में मदद मिलेगी।

तुम्हारे बाप भी नहीं रोक सकते, तेलंगाना में मंत्री की बेटी ने ही दे डाली सीएम रेवंत रेड्डी को चुनौती



हैदराबाद, एजेंसी। तेलंगाना कांग्रेस में चल रही बगावत अब खुलकर सामने आ गई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री की बेटी ने उन पर सार्वजनिक रूप से हमला किया है। रेड्डी सरकार में मंत्री कोंडा सुरेशा की बेटी कोंडा सुष्मिता ने मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दी है। पारकल में बोलते हुए बुधवार को सुष्मिता ने न केवल मौजूदा विधायक रेवूरी प्रकाश रेड्डी के लिए रेवंत रेड्डी के समर्थन को चुनौती दी, बल्कि उनके अधिकार पर भी सवाल उठाए और उन्हें चुनावी चुनौती दी।

पारकल की विधायक तो मैं ही बनूंगी: सुष्मिता की बातें टिकट को लेकर होने वाले आम झगड़े से कहीं आगे की हैं। मौजूदा विधायक को मुख्यमंत्री का सार्वजनिक समर्थन मिलने पर उन्होंने कहा, «दो साल का इंतजार क्यों? उनसे अभी इस्तीफा देने को कहिए! उनसे कहिए कि इस्तीफा दें और चुनाव लड़ें!» इसके बाद उन्होंने ऐलान किया, चाहे आप आएँ, आपके पिता आएँ या आपके दादा आएँ, पारकल की विधायक मैं ही बनूंगी।

अहंकारी हैं रेवंत रेड्डी: उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर अपना हमला और तेज करते हुए पूछा, «मेरा टिकट तय करने वाले रेवंत कौन होते हैं? उन्होंने रेवंत रेड्डी पर अहंकार का आरोप लगाया और कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस टीडीपी कांग्रेस बन गई है। साथ ही यह भी दावा किया कि पार्टी के मूल नेता पार्टी की दिशा से नाबुझ हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के भाई से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जमीन सौदे का भी आरोप लगाया और चेतावनी दी कि वह रेवंत रेड्डी के परिवार से जुड़े अन्य कथित घोटालों का भी पर्दाफाश कर सकती हैं।

तेल-रासायनिक आपदा से निपटने की तैयारी परखेगा बंगाल, 21 अगस्त को पांच जिलों में माॅक ड्रिल

कोलकाता, एजेंसी। बंगाल के होटलों में लगातार हुए दो बड़े अग्निकांड की घटनाओं में 18 लोगों की मौत से राज्य सरकार चिंतित है। इन घटनाओं से सबक लेते हुए तेल एवं रासायनिक आपदा की स्थिति में राज्य की तैयारियों और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को परखने के लिए बंगाल सरकार का आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग 21 अगस्त को राज्यस्तरीय माॅक अभ्यास आयोजित करेगा। निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य के पांच जिलों में स्थित प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अभ्यास के लिए चुना गया है। इसमें संबंधित जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन तंत्र और औद्योगिक इकाइयों की आपात स्थिति से निपटने की क्षमता को परखा जाएगा। राज्य सचिवालय नवाब की ओर से बुधवार को एक बयान में बताया गया कि राज्यस्तरीय माक अभ्यास के लिए नदिया जिले में ईंडियन आयल (आइओसीएल) के एलपीजी बाटलिंग प्लांट, पश्चिम बर्द्धमान में सेल के दुर्गापुर स्टील प्लांट, पूर्व बर्द्धमान में मैट्रिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, मालदा में आईओसीएल के एलपीजी बाटलिंग प्लांट तथा दक्षिण 24 परगना में बीपीसीएल प्रतिष्ठान को शामिल किया गया है। अभ्यास के दौरान



तेल और रासायनिक पदार्थों से जुड़ी संभावित दुर्घटनाओं की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य, आपात प्रतिक्रिया, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और प्रभावित क्षेत्र में त्वरित कार्रवाई की तैयारियों का आकलन किया जाएगा।

आपदा की स्थिति में समन्वित कार्रवाई की होगी जांच: इस माक अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक आपदा की स्थिति में प्रशासन, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और संबंधित आपात सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। अभ्यास के माध्यम से संभावित कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि तेल या रासायनिक दुर्घटना की स्थिति में जान-माल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

हिमाचल में 25 साल बाद फिर शुरू होगी लॉटरी, किस्मत आजमाने से पहले जान लें नियम और शर्तें; खास मौके पर निकलेंगे बंपर ड्रॉ



शिमला, एजेंसी। हिमाचल में करीब 25 साल से बंद लॉटरी व्यवस्था को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंच गई है। वित्त विभाग के तहत निदेशालय कोषागार, लेखा एवं लॉटरी ने पेपर और ऑनलाइन लॉटरी की बिक्री के लिए सोल सेलिंग एजेंट नियुक्त करने को ई-टेंडर जारी कर दिया है। सरकार ने लॉटरी संचालन को डिजिटल, पारदर्शी और कड़े नियमन के तहत चलाने की तैयारी की है। टेंडर की शर्तों के मुताबिक प्रतिदिन अधिकतम 12 लॉटरी ड्रॉ आयोजित किए जा सकेंगे। इसके अलावा साल में तीन बंपर ड्रॉ होंगे। राष्ट्रीय महत्व के दिनों 26 जनवरी, 15 अगस्त और दो अक्टूबर को ड्रॉ आयोजित नहीं किया जाएगा। सभी ड्रॉ हिमाचल प्रदेश के किसी सार्वजनिक स्थान पर ड्रॉ जजों की मौजूदगी में होंगे। स्वतंत्र पंचवैश्वकों और अधिकृत अधिकारियों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। डिजिटल ड्रॉ सिस्टम अपनाने का विकल्प भी रखा गया है।

सरकार को हर साल करोड़ों का राजस्व

सोल सेलिंग एजेंट को सरकार को प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये लाइसेंस फीस देनी होगी। इसमें हर साल पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा एजेंट को न्यूनतम छह करोड़ रुपये की वार्षिक गारंटीड राशि (एमजीए) देनी होगी। लॉटरी के कुल कारोबार पर कम से कम दो प्रतिशत रेवेन्यू शेयर की बोली लगानी होगी। सबसे अधिक रेवेन्यू शेयर की बोली लगाने वाले तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता को एच-1 घोषित किया जाएगा। सरकार ने एजेंट के लिए 30 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अनिवार्य की है। यह राशि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी अथवा एफडीआर के रूप में देनी होगी। प्रत्येक पेपर या ऑनलाइन ड्रॉ के लिए पांच हजार रुपये ड्रॉ खर्च भी एजेंट को देना होगा।

दो साल का होगा अनुबंध: चयनित एजेंट के साथ दो वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। प्रदर्शन संतोषजनक रहने पर सरकार अपने विवेक से इसे दो वर्ष और बढ़ा सकती है। लॉटरी संचालन के लिए एजेंट को स्पेशल पर्पज क्लिक (एसपीवी) गठित करना होगा। बिक्री, वितरण, डिजिटल भुगतान, रिकॉर्ड-कीपिंग और वित्तीय लेनदेन इसी व्यवस्था के तहत किए जाएंगे। इससे प्रत्येक लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड और ऑडिट ट्रेल उपलब्ध रहेगा। **दो करोड़ ईएमडी, पांच लाख टेंडर फीस:** टेंडर में भाग लेने वाली कंपनियों को दो करोड़ रुपये की ईएमडी जमा करनी होगी। टेंडर फीस पांच लाख रुपये निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले तकनीकी बोली की आधार पर कंपनियों के अनुभव, वित्तीय क्षमता और तकनीकी योग्यता की जांच होगी।

यूनएससी में भारत की दो टूक: विकासशील देशों को मिले अधिक प्रतिनिधित्व, आतंकवाद पर राजनीति को लेकर क्या कहा

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूनएससी) के काम करने के तरीकों पर खुली चर्चा हुई। इस चर्चा में भारत की राजदूत योजना पटेल ने देश का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों को सुरक्षा परिषद में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग करता है। उन्होंने कहा कि अस्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में सार्थक योगदान देने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को दस्तावेजों तक पहुंच के मामले में एक जैसे अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए।

राजदूत योजना पटेल ने क्या कहा: योजना पटेल ने कहा कि जो देश सीधे तौर पर किसी मुद्दे से जुड़े हैं, उन्हें सुरक्षा परिषद के फैसले लेने की व्यवस्था में भी शामिल किया जाना चाहिए। खासकर शांति स्थापना से जुड़े सभी बड़े सवाल में उनकी भूमिका होनी चाहिए। इनमें मिशन का काम क्या होगा और उसके लिए कितने संसाधन दिए जाएंगे जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज संख्या- 507 में उचित बदलाव किया जाना चाहिए।

ईरान पर होगी सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई: ट्रंप ने दी धमकी, मदद करने वाले देशों को चेताया; क्या बढ़ेगा तनाव

वाशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त आर्थिक कार्रवाई की धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का सबसे बड़ा मौका दिया गया था। लेकिन उसने इसे गंवा दिया। ट्रंप ने कहा, इस्लामी गणराज्य ईरान को किसी समझौते के लिए मुझसे ज्यादा बड़ा मौका किसी ने नहीं दिया। दुख की बात है कि उन्होंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। इसलिए आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई की घोषणा कर रहा हूँ। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। उसकी वायु सेना नष्ट हो गई है। उसकी सैन्य फैक्टरियां मलबे में बदल



गई हैं। ईरान की मुद्रा बेकार हो गई है और देश बेहद कमजोर स्थिति में है। **ईरान की मदद करने वाले देशों पर भी कार्रवाई:** ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद देगा, उसे भी बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसमें वित्तीय संस्थान, कारोबार, हवाई अड्डे और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने तेल की तस्करी, स्वैप लाइन, नकद लेनदेन, एक्सचेंज हाउस, जहाजों

के पंजीकरण और ईरान की मदद करने वाली छिपी हुई (शेल) कंपनियों को तुरंत रोकने की बात कही। **सहयोगी देशों से अमेरिका के साथ आने की अपील:** ट्रंप ने इसे ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक हमले का दिन बताया। उन्होंने अमेरिका के सहयोगी देशों से ईरान को अलग-थलग करने और उसके खतरे को खत्म करने में साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईरान इस समय बेहद कमजोर स्थिति में है। उन्होंने दावा किया कि ये ऐतिहासिक कदम ईरान को और दुनियाभर में आतंक फैलाने की उसकी क्षमता को बुरी तरह कमजोर कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा।

अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाया: अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के पिछले हफ्ते इसी तरह बयान दिया था। बेसेंट ने कहा था कि अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिशें बढ़ाएगा। इस रणनीति में अमेरिकी नौसैनिक नावें भी शामिल हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय %ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी% नाम से प्रतिबंध अभियान भी चला रहा है। इसका मकसद लक्षित कार्रवाई के जरिये ईरान के पैसे जुटाने के स्रोतों को बंद करना है।

ईरान के खिलाफ युद्ध कब शुरू हुआ: युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इस्राइल के हमलों के साथ हुई।

अमेरिका में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, भागवत के यूएस दौरे पर यूएससीआईआरएफ सख्त; बोला- संघ नेताओं को न मिले सम्मान



बताया, जिसके सहयोगी संगठनों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले करने के आरोप लगते रहे हैं। महमूद की ये टिप्पणियां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिकन दौरे से कुछ हफ्ते पहले सामने आई हैं। भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदूज़ फॉर एगेजमेंट एंड डायलॉग की ओर से आयोजित यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य हैं। उन्होंने आरएसएस को एक %अंबेला ऑर्गनाइजेशन यानी ऐसा मुख्य संगठन

मिल्स ने कहा कि आरएसएस नेताओं को, भले ही वे भारत सरकार से जुड़े हों, हाई-लेवल मीटिंग या राजनयिक सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बजाय, अमेरिकी सरकार को उन आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान देना चाहिए, जो फीडबैक ऑफ रिलिजन ऑर बिनीफिट यानी धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। यूएससीआईआरएफ ने आसिफ महमूद और जॉन मिल्स की इन टिप्पणियों को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। **महमूद ने आरएसएस को लेकर**

क्या कहा: महमूद ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य हैं। यह भारत का एक मुख्य संगठन है, जिसके सहयोगी समूहों ने ईसाइयों और मुसलमानों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। अब आरएसएस नेता मोहन भागवत अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। **हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी उठाए सवाल:** एडवोकेसी ग्रुप हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि मोहन भागवत के दौरे को मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ आरएसएस नेटवर्क से जुड़े हिंसा के आरोपों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इस एडवोकेसी ग्रुप ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि %एकता% का उसव धार्मिक श्रेष्ठता की राजनीति को छिपा नहीं सकता। **मार्च की रिपोर्ट में भी भारत पर निशाना:** मार्च में यूएससीआईआरएफ की सालाना रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता

के कथित उल्लंघन को लेकर भारत की आलोचना की गई थी। रिपोर्ट में आरएसएस और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सहित कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं पर टारगेटेड प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया गया था। यूएससीआईआरएफ ने इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया था। **भारत ने यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट खारिज की:** भारत ने यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। भारत का कहना है कि यह संस्था लगातार देश की गलत और चुनिंदा तस्वीर पेश करती है और उसकी रिपोर्ट संदिग्ध स्रोतों और वैचारिक नैरेटिव पर आधारित होती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 16 मार्च को एक बयान में कहा था कि यूएससीआईआरएफ को भारत की चुनिंदा आलोचना करने के बजाय अमेरिका में हिंदू मंदिरों में तोड़-फोड़ और हमलों की चिंताजनक घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए।

अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूकता का संदेश: मझौली महाविद्यालय में कार्यशाला और प्रतियोगिताएं



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली में उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में 'भारतीय ज्ञान परंपरा एवं अक्षय ऊर्जा' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई प्राचार्य डॉ. गीता भारती के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के संबंध में जानकारी दी गई कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अमित कुमार मिश्रा ने कहा कि भारतीय चिंतन में प्रकृति और ऊर्जा को जीवन का अभिन्न आधार माना गया है सूर्य, वायु और अग्नि के महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा सतत विकास की आधारशिला है सह-वक्ता राकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि अक्षय ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है इसके लिए जन-जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है प्राचार्य डॉ. गीता भारती ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकृति के साथ संतुलन और संधारण पर आधारित है उन्होंने विद्यार्थियों से प्रकृति संरक्षण और संसाधनों के संतुलित उपयोग को व्यवहार में अपनाने का आह्वान किया कार्यशाला के अंतर्गत निबंध लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। निबंध में दीक्षा गुप्ता प्रथम, संतोषी साहू द्वितीय और आशीष कुमार यादव तृतीय रहे ।

ब्यूहारी सिविल अस्पताल में अनशन खत्म: 25 दिन में स्त्री रोग विशेषज्ञ, सोनोग्राफी और डायलिसिस सुविधा शुरू करने का आश्वासन



मीडिया ऑडिटर, शहडोल (निप्र)। ब्यूहारी सिविल अस्पताल में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर स्वतंत्रता दिवस से चल रहा आमरण अनशन गुस्वार सुबह प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया प्रशासन ने अनशनकारी को भरोसा दिलाया कि अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ, सोनोग्राफी और डायलिसिस जैसी सुविधाएं उपलब्ध करने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और 25 दिनों के भीतर व्यवस्थाएं लागू करने का प्रयास किया जाएगा अनशन का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करना था लंबे समय से स्त्री रोग विशेषज्ञ, सोनोग्राफी और डायलिसिस की सुविधा नहीं होने के कारण स्थानीय

मरीजों को उपचार के लिए शहडोल सहित अन्य शहरों का रुख करना पड़ता था। प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

जल्द जॉइन करेंगी स्त्री रोग विशेषज्ञ: प्रशासन के अनुसार ब्यूहारी सिविल अस्पताल के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. बबिता खरे का स्थानांतरण किया जा चुका है हालांकि उन्होंने अभी अस्पताल में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही उनके जॉइन करने की उम्मीद है उनके आने से महिला मरीजों को स्त्री रोग संबंधी उपचार के लिए दूररे शहरों में जाने से रहत मिलने की संभावना है।

टोकन से नि:शुल्क होगी सोनोग्राफी: सोनोग्राफी सुविधा को

लेकर प्रशासन ने बताया कि अस्पताल आने वाले मरीजों को डॉ. आर.एस. पांडे के यहां सोनोग्राफी के लिए टोकन जारी किए जाएंगे टोकन के आधार पर सिविल अस्पताल के मरीजों की सोनोग्राफी नि:शुल्क कराई जाएगी इसके लिए होने वाले भुगतान की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा की जाएगी इससे मरीजों को निजी स्तर पर सोनोग्राफी करने के खर्च से रहत मिलेगी।

डायलिसिस सुविधा की प्रक्रिया शुरू: ब्यूहारी सिविल अस्पताल में डायलिसिस सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है इसके शुरू होने के बाद किडनी के मरीजों को नियमित डायलिसिस के लिए शहडोल या अन्य दूरस्थ शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी हालांकि प्रशासन ने अभी डायलिसिस सेवा शुरू होने की निश्चित तारीख घोषित नहीं की है। अस्पताल में ड्रेजिंग, ब्लेडिंग और पट्टी सहित अन्य जरूरी चिकित्सा सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दिया गया है।

भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस में विविध कार्यक्रम: विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति किया जागरूक



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस, संजय गांधी स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, सीधी में ऊर्जा संरक्षण और अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अक्षय ऊर्जा के महत्व, इसके विभिन्न स्रोतों और ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई

कार्यक्रम का विषय परिचय डॉ. बृजेश सिंह चौहान ने कराया। इस दौरान 'प्राचीन ग्रंथों में अक्षय ऊर्जा से संबंधित उपबंध' विषय पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। सहायक प्राध्यापक रसायन विज्ञान डॉ. उषाकांत साहू ने अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान समय में अक्षय ऊर्जा पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है उन्होंने कहा कि समय रहते ऊर्जा संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के प्रति जागरूकता नहीं बढ़ाई गई तो भविष्य में ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अक्षय ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर: डॉ. सत्य प्रकाश शुक्ला ने कहा कि अक्षय ऊर्जा सभी के लिए महत्वपूर्ण पूंजी है इसका संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है उन्होंने विद्यार्थियों से ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को रोकने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय ऋषि-मुनियों द्वारा अक्षय ऊर्जा के उत्पादन एवं संरक्षण

की अवधारणा पर आधारित लघु चलचित्र और चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई इसके माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रकृति, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े विचारों से परिचित कराया गया।

निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने लिया भाग: विद्यार्थियों की रचनात्मक सहभागिता बढ़ाने के लिए 'भारतीय ज्ञान परंपरा एवं अक्षय ऊर्जा' विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई इसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. के.एस. नेताम ने कहा कि वर्तमान समय में ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है विद्यार्थियों को अक्षय ऊर्जा के महत्व से जोड़ना भविष्य में जिम्मेदार और पर्यावरण-संवेदनशील समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है कार्यक्रम के अंत में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने ऊर्जा संरक्षण तथा अक्षय ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग का संकल्प लिया।

सीधी शहर में सीवर लाइन सर्वेक्षण शुरू: डीपीआर तैयार होने के बाद होगा निर्माण, जलभराव और जल निकासी की समस्या कम होने की उम्मीद



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। शहर में बेहतर और व्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हो गई है विधायक रीती पाठक के प्रयासों से

सीधी शहर में सीवर लाइन व्यवस्था विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है इसी क्रम में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीयूडीसी) की टीम ने सीवर

लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया है सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया जाएगा आवश्यक स्वीकृतियां और अन्य प्रक्रियाएं

कलेक्टर ने सर्वेक्षण टीम से ली जानकारी: एमपीयूडीसी की टीम द्वारा शुरू किए गए सर्वेक्षण कार्य के संबंध में कलेक्टर विकास मिश्रा ने टीम से चर्चा की उन्होंने सीधी शहर की वर्तमान जल निकासी व्यवस्था, प्रमुख जलभराव वाले क्षेत्रों और भविष्य की आवश्यकताओं की जानकारी ली कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वेक्षण का कार्य व्यापक और तकनीकी रूप से सटीक तरीके से किया जाए ताकि इसके आधार पर तैयार होने वाली डीपीआर शहर की मौजूदा जरूरतों के साथ भविष्य के विस्तार को भी ध्यान में रखे कलेक्टर ने कहा कि सीवर लाइन की योजना तैयार करते समय शहर के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र का समुचित अध्ययन जरूरी है

इसके लिए मौजूदा नालियां, जल निकासी मार्गों, जलभराव वाले स्थानों और संभावित सीवर नेटवर्क के मार्गों का तकनीकी अध्ययन करने के निर्देश दिए गए। **जलभराव वाले क्षेत्रों का होगा अध्ययन:** सर्वेक्षण के दौरान एमपीयूडीसी की टीम शहर की भौगोलिक स्थिति और मौजूदा जल निकासी व्यवस्था का अध्ययन कर रही है इसके साथ ही भविष्य में विकसित किए जाने वाले सीवर नेटवर्क के तकनीकी पहलुओं का भी परीक्षण किया जा रहा है सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन क्षेत्रों में सीवर लाइन की आवश्यकता है और नेटवर्क का स्वरूप किस प्रकार रखा जाना उपयुक्त होगा।

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन एवं शैल्वी हॉस्पिटल जबलपुर के संयुक्त तत्वावधान में 22 अगस्त को जिला अस्पताल सीधी में नि:शुल्क कैंसर रोग परामर्श शिविर आयोजित किया जाएगा शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों की जांच कर आवश्यक परामर्श देंगे उमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे ने बताया कि शिविर का उद्देश्य महिलाओं में स्तन कैंसर तथा आमजन में मुख और गले के कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना है साथ ही प्रारंभिक स्तर पर बीमारी की पहचान कर समय पर उपचार सुनिश्चित

करना भी शिविर का प्रमुख उद्देश्य है शिविर में शैल्वी हॉस्पिटल जबलपुर की रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. मालती भगत और कंसल्टेंट ऑन्कोसर्जन डॉ. प्रसांत जैन मरीजों की जांच एवं परामर्श करेंगे। **महिलाओं को स्व-परीक्षा की जानकारी:** शिविर के दौरान महिलाओं को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी स्वयं स्तन परीक्षण की विधि भी समझाई जाएगी महिलाओं को मासिक धर्म समाप्त होने के 5 से 7 दिन बाद नियमित रूप से स्व-परीक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार क्लीनिकल स्तन जांच कराने की सलाह दी गई है।

रीवा जिला कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न: संगठन सुदृढ़ीकरण और जनआंदोलनों को लेकर बनी रणनीति



गया। बैठक में ट्रस्ट के गठन एवं संचालन के संबंध में सदस्यों से जानकारी ली गई सदस्यों ने बताया कि जिले में पार्टी से संबंधित कोई ट्रस्ट वर्तमान में संचालित नहीं है इस पर कहा गया कि यदि भविष्य में किसी ट्रस्ट के गठन की आवश्यकता महसूस होती है, तो उसका प्रस्ताव आगामी बैठक में रखा जाए।

जिला कांग्रेस कार्यालय का निर्माण जारी: बैठक में

विधानसभा प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट प्रस्तुत की त्योंधर, सिरमौर और गुढ़ विधानसभा क्षेत्रों में अधिकांश सत्यापन कार्य पूरा होने की जानकारी दी गई शेष क्षेत्रों में भी सत्यापन कार्य को 8 जुलाई तक पूरा करने का निर्णय लिया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर की कमेटियों को सक्रिय और व्यवस्थित करना जरूरी है। इसके लिए सत्यापन प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया।

सोशल मीडिया पर अनुशासनहीनता पर चिंता: बैठक में पार्टी के विरुद्ध सोशल मीडिया पर होने वाली अनुशासनहीन गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई ऐसे मामलों की निगरानी और समीक्षा के लिए तीन या पांच

सदस्यीय अनुशासन समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। समिति सोशल मीडिया से जुड़े मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेगी।

हर माह होंगे कम से कम दो जनआंदोलन: बैठक में स्थानीय जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन तेज करने का भी निर्णय लिया गया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रमों के साथ स्थानीय मुद्दों को जोड़ते हुए प्रत्येक माह कम

से कम दो जनआंदोलन आयोजित करने की रणनीति बनाई गई प्रारंभिक चरण में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम कार्यालयों में जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन किए जाएंगे आंदोलनों की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष इंजी. राजेन्द्र शर्मा को सौंपी गई। वे ब्लॉक अध्यक्षों, विधानसभा प्रभारियों और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद आंदोलन की तिथियां घोषित करेंगे।

संगठन मजबूत करने का



प्रशिक्षित ग्राम सामाजिक एनिमेटरों से ही कराया जाए सोशल ऑडिट: शहडोल में संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन



मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। केंद्र और राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) का काम पूर्व से चर्यनित और प्रशिक्षित ग्राम सामाजिक एनिमेटरों से ही करने की मांग को लेकर ग्राम विकास सामाजिक एनिमेटर संघ ने कलेक्टर शहडोल को ज्ञापन सौंपा संघ ने मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में बाहरी व्यक्तियों, निजी एजेंसियों और अप्रशिक्षित लोगों से सोशल ऑडिट करने पर आपत्ति जताई है संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि ग्राम सामाजिक एनिमेटरों का चयन शासन की निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया

गया है चयन के बाद उन्हें सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित विधिवत प्रशिक्षण भी दिया गया है ये एनिमेटर मनरेगा सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के सोशल ऑडिट में पहले से काम करते आ रहे हैं संघ ने ज्ञापन में कहा कि ग्राम सामाजिक एनिमेटरों को ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीणों की समस्याओं की जानकारी है ऐसे में उनके अनुभव का उपयोग सामाजिक अंकेक्षण के कार्य में किया जाना अधिक प्रभावी और उपयोगी हो सकता है संघ का दावा है कि प्रशिक्षित एनिमेटरों को हटकर बाहरी एजेंसियों या नए लोगों को जिम्मेदारी

देने से पहले से उपलब्ध अनुभवी मानव संसाधन का उपयोग नहीं हो पाएगा इससे न केवल प्रशिक्षित लोगों के अनुभव की अनदेखी होगी बल्कि नए लोगों को प्रशिक्षण देने में समय और सरकारी धन भी खर्च होगा।

निजी एजेंसियों को काम देने का विरोध: ग्राम विकास सामाजिक एनिमेटर संघ ने विभिन्न योजनाओं के सोशल ऑडिट का काम निजी एजेंसियों, बाहरी व्यक्तियों अथवा अन्य संस्थाओं को दिए जाने का विरोध किया है संघ ने शासन से मांग की है कि सोशल ऑडिट के लिए पहले से चर्यनित और प्रशिक्षित ग्राम सामाजिक एनिमेटरों को ही प्राथमिकता दी जाए ज्ञापन में कहा गया कि इन एनिमेटरों ने वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया है उनके अनुभव और प्रशिक्षण का लाभ शासन को लेना चाहिए संघ ने प्रशिक्षित मानव संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने की मांग की है।

पहली बारिश में ही बिजली विभाग की खुली पोल! कई सर्विस स्टेशन जलमग्न, दो में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले में हुई पहली बारिश ने बिजली विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं बारिश के बाद रहता, करहिया, इटहा-छीजवार और अमहिया सहित कई क्षेत्रों के विद्युत सर्विस स्टेशनों में पानी भर गया जलभराव के कारण विद्युत व्यवस्था प्रभावित

महत्वपूर्ण इन केंद्रों में जलभराव की स्थिति बनी रहने से उपकरणों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है इटहा-छीजवार क्षेत्र में भी बिजली लाइन प्रभावित होने से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

जल निकासी व्यवस्था पर उठे सवाल: स्थानीय लोगों का कहना है कि मानसून आने से पहले विद्युत सर्विस स्टेशनों में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इसके अलावा जलभराव वाले स्थानों पर जरूरी रखरखाव और सुरुक्षा के उपाय किए जाने की आवश्यकता थी पहली बारिश में ही कई सर्विस स्टेशनों में पानी भरने से विभाग की मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों के

मुताबिक यदि शुरुआती बारिश में ही बिजली व्यवस्था प्रभावित हो रही है, तो आने वाले दिनों में लगातार और तेज बारिश होने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है खासकर उन क्षेत्रों में जहां सर्विस स्टेशनों के आसपास पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है वहां विद्युत आपूर्ति बाधित होने का खतरा बना रहेगा।

जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग: स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जलमग्न सर्विस स्टेशनों से तत्काल पानी निकासी करने की मांग की है इसके साथ ही विद्युत उपकरणों की सुरुक्षा जांच करने और प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने की मांग भी उठाई गई है।

22 अगस्त को जिला अस्पताल सीधी में नि:शुल्क कैंसर परामर्श शिविर: स्तन, मुख और गले के कैंसर की होगी जांच

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन एवं शैल्वी हॉस्पिटल जबलपुर के संयुक्त तत्वावधान में 22 अगस्त को जिला अस्पताल सीधी में नि:शुल्क कैंसर रोग परामर्श शिविर आयोजित किया जाएगा शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों की जांच कर आवश्यक परामर्श देंगे

उमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे ने बताया कि शिविर का उद्देश्य महिलाओं में स्तन कैंसर तथा आमजन में मुख और गले के कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना है साथ ही प्रारंभिक स्तर पर बीमारी की पहचान कर समय पर उपचार सुनिश्चित

करना भी शिविर का प्रमुख उद्देश्य है शिविर में शैल्वी हॉस्पिटल जबलपुर की रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. मालती भगत और कंसल्टेंट ऑन्कोसर्जन डॉ. प्रसांत जैन मरीजों की जांच एवं परामर्श करेंगे।

महिलाओं को स्व-परीक्षा की जानकारी: शिविर के दौरान महिलाओं को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी स्वयं स्तन परीक्षण की विधि भी समझाई जाएगी महिलाओं को मासिक धर्म समाप्त होने के 5 से 7 दिन बाद नियमित रूप से स्व-परीक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार क्लीनिकल स्तन जांच कराने की सलाह दी गई है।

देश भर में 'विरोध' एक असरदार मुहान्वा और हथियार बन गया है। इसे सामुदायिक प्रयोग भी कह सकते हैं। लगता है कि कष्ट, अन्याय, शोषण इतनी पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं कि आखिरी विकल्प 'विरोध' ही बचा है। कई बार यह भी एहसास होता है कि 'विरोध' की जमात में अचानक महात्मा गांधी की चेतना जागृत हो उठी है और वह व्यवस्था की चूल्हे हिला देने पर आमादा है। बिल्कुल शांतिपूर्ण, संयमी, इच्छ-शक्ति से भरपूर, व्यवस्था के प्रतिरोध और धमकियों को झेलते हुए 'विरोध' किए जा रहे हैं। वे कामयाब होकर अपना मकसद भी हासिल कर रहे हैं। यह जमात दिल्ली के जंतर-मंतर या रामलीला मैदान अथवा किन्हीं 'कॉकरोचों' से प्रेरित नहीं है, बल्कि	दमन, भ्रष्टाचार और शोषण ने इसे संघर्ष करने को बाध्य किया है। दो उदाहरण अभूतपूर्व और अकल्पनीय लगते हैं। बारिश में भीगती स्कूली छात्राओं ने मुख्य सड़क अवरुद्ध कर दी, क्योंकि वे स्कूल की नकारा, उपेक्षित व्यवस्थाओं से तंग आ चुकी थीं। न अध्यापक, न सुरक्षित क्लास रूम, न स्वच्छ शौचालय और न ही पोषक दोपहर का भोजन..! इस विरोध-प्रदर्शन ने सरकार और प्रशासन को हिला दिया, संबद्ध अधिकारी एकदम दौड़े चले	आए और छात्राओं को आश्वस्त किया। विरोध समाप्त कर दिया गया। दूसरा उदाहरण बाबा अंबेडकर की जन्मस्थली महु (मप्र) के पास का है। झार जिले के निसरपुर में 'माता शबरी आवासिय कन्या छात्रावास' में 60 छात्राओं की व्यवस्था थी, लेकिन वहां करीब 150 छात्राओं को 'भेड़-बकरियों' की तरह रूस कर रहने को विवश किया गया था। बीते रविवार की देर रात	में 9वीं-11वीं कक्षा की 40 छात्राएं खिड़कियों से बाहर कूदें, नंगे पांव चलती रहीं और पुलिस स्टेशन तक पहुंच गईं। रात के अंधेरे में ही एसडीओ (पुलिस) और तहसीलदार दौड़े चले आए और छात्राओं की छात्रावास की वार्डन और कार्यवाहक प्रिंसिपल को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया। कमोबेश व्यवस्था को विरोध के सामने	झुकना पड़ा। दरअसल ये तमाम 'विरोध' दिल्ली, रांची, पटना, लखनऊ, कोलकाता के विभिन्न विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों से भिन्न हैं। इन्हें न तो नौकरी चाहिए, न ही अभी उम्र है और न पेपरलकी या परीक्षा रद्द किए जाने के कारण भविष्य दांव पर है। इनका विरोध बुनियादी व्यवस्थाओं को लेकर है। बहरहाल रांची में अनशन, आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन विरोध, संघर्ष अब भी जारी है। अब वे 1932 नौकरीपेशा चेहरे आंदोलनरत हैं, जिनकी नौकरी छिन रही है।
---	--	---	--	--

सत्ताधारी दल के संगठन की चुनौतियां

राजीव सचान

अध्यक्ष बनने के लगभग सात महीने बाद नितिन नवीन की टीम घोषित हो गई। इसकी चर्चा इसलिए भी अधिक हो रही है, क्योंकि इसमें विलंब हुआ। किसी के लिए समझना कठिन है कि भाजपा अध्यक्ष को अपनी नई टीम बनाने में इतनी देर क्यों हुई? इस देरी का कारण जो भी हो, यह टीम एक ऐसे समय गठित हुई है, जब मोदी सरकार विपक्ष के आक्रामक तेवरों का सामना कर रही है। राजनीतिक इरादों से लैस नजर आने वाली काकरोच जनता पार्टी की ओर से नीट पेपर लीक मामले में आंदोलन छेड़ने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र पर अड़ जाने के बाद जो माहौल बना, उसका विपक्ष ने जमकर लाभ उठाया। इसी के नतीजे में संसद का मानसून सत्र न के बराबर चल सका।
सरकार जिस तरह संसद में गतिरोध तोड़ने में नाकाम रही, उससे यह स्पष्ट निकला कि विपक्ष उस पर भारी पड़ा। सरकार यह भांप नहीं सकी कि विपक्ष केवल गोल पोस्ट बदलने ही नहीं, बल्कि उसे लेकर भाग खड़े होने की रणनीति पर चल रहा है।
नितिन नवीन की टीम को तत्काल प्रभाव से सक्रिय होना होगा, क्योंकि आनेले वर्ष कम से कम सात राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश भी है। नितिन नवीन की टीम के सामने पार्टी और साथ ही केंद्र सरकार एवं अपनी राज्य सरकारों के पक्ष में ही नैरेटिव बनाने की चुनौती है। स्वाभाविक रूप से यह चुनौती उन राज्यों में अधिक होगी, जहां उसकी अपनी सरकारें हैं और जहां चुनाव भी निकट हैं, क्योंकि इन सरकारों के कामकाज के लिए वह उसी तरह जवाबदेह होगी, जैसे मोदी सरकार के कामकाज के लिए। नि:संदेह सत्ताधारी दलों के संगठनों को अपनी सरकारों का सहयोग और संरक्षण मिलने से कुछ सुविधा होती है, लेकिन जहां सत्ता से बाहर खड़े विपक्षी दलों को केवल विरोधी दलों की सरकारों की आलोचना-निंदा करना होता है, वहीं सत्ताधारी दलों के संगठनों को इसका प्रतिकार करने के साथ अपनी सरकार की नाकामियों पर भी जवाब देना होता है। यदि कोई सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी न उतर पा रही हो और उसकी रीति-नीति से जनता में असंतोष बढ़ रहा हो तो उसका संगठन कितना भी सशक्त और तेज-तरंग नेताओं से लैस क्यों न हो, उसे अपने पक्ष में नैरेटिव खड़ा करने में कठिनाई होगी। दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद युवा और खासकर जेन-जी चर्चा में हैं। वे भाजपा के साथ अन्य सभी दलों की प्राथमिकता में आ गए हैं। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने युवाओं और नौजवानों का उल्लेख कई बार किया। इसी के कुछ दिन बाद नितिन नवीन की टीम घोषित हुई, लेकिन उनकी टीम की घोषणा के कुछ ही घंटे पहले खबर आ चुकी थी कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से आयोजित करने जाने वाली यूजीसी-नेट के तीन विषयों की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। यह इसलिए स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि अनुवाद में गलतियां पाई गईं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप और अस्सिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता के साथ पीएचडी में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों में उसी एनटीए की ओर से तब गड़बड़ियां हुईं, जब नीट पेपर लीक के कारण उसकी फजीहत हो चुकी थी और उसकी तपिश मोदी सरकार को भी झेलनी पड़ी। इसे लापरवाही की पराकाष्ठा कहेंगे कि जिन तीन विषयों की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी, उनके प्रश्न पत्रों में टाइपिंग की भी गलतियां थीं और कई प्रश्न ऐसे थे, जो पहले पूछे जा चुके थे। साफ है कि एनटीए का नाकारापन अब भी कायम है। या तो उसके अधिकारी लापरवाह हैं या फिर नाकारा। आखिर एनटीए के ऐसे कामकाज के बाद नितिन नवीन की टीम युवाओं को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकती है? उनकी टीम की घोषणा के पहले आई यह खबर भी चर्चा में रही कि नए बने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे में एक माह के अंदर ही इतने पट्टे हो गए कि उन्हें गिनना भी कठिन हो रहा है।

‘विरोध’ से झुकीं त्यवस्थाएं

संपादकीय
आए और छात्राओं को आश्वस्त किया। विरोध समाप्त कर दिया गया। दूसरा उदाहरण बाबा अंबेडकर की जन्मस्थली महु (मप्र) के पास का है। झार जिले के निसरपुर में 'माता शबरी आवासिय कन्या छात्रावास' में 60 छात्राओं की व्यवस्था थी, लेकिन वहां करीब 150 छात्राओं को 'भेड़-बकरियों' की तरह रूस कर रहने को विवश किया गया था। बीते रविवार की देर रात

भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता

भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने के साथ ही विकसित भारत के लिए ज्ञान-लोक गढ़ने वाली भी है।भारतीय ज्ञान परंपरा पर अध्ययन, अध्यापन और शोध की प्रक्रिया भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रारंभ हो गई है। कई विश्वविद्यालयों में इस विषय पर अध्ययन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और उच्च शिक्षण संस्थानों में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं।

है। इसमें उदाहरण और अनुभव भी शामिल हैं, जो हमारे पाठ्यक्रमों में आ रहे हैं। इसे केवल एक विषय के रूप में देखने की ग्रंथि से हमें मुक्त होना होगा।

भारतीय शिक्षा और विमर्श जगत की दूसरी समस्या यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध और संकलन के क्षेत्र में अभी कम काम हुआ है, जिसके कारण हमारे पास अध्ययन सामग्री का अभाव है। इस कमी को समझते हुए विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान अपने-अपने तरीके से इस दिशा में कार्यरत हैं। समाज विज्ञान से जुड़े शिक्षा संस्थानों में भारतीय समाज के ज्ञान, मेधा, तकनीकी पर शोध, संकलन और अध्ययन सामग्री बनाने का कार्य अभी पर्याप्त गुणात्मकता के साथ प्रारंभ हुआ है। अनेक विद्वान और समाजशास्त्री इस दिशा में कार्यरत हैं। इन शोधों का परिणाम शोध ही दिखेगा। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान ने पाठ्यपुस्तक निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित पाठ्यपुस्तकें बनाने के अभियान को खासा महत्व दिया है। अन्य विश्वविद्यालयों को भी भारतीय ज्ञान परंपरा पर ज्ञान सृजन की परियोजना पर काम करना होगा। शिक्षा मंत्रालय में भारतीय ज्ञान परंपरा पर ज्ञान सृजन की

प्रक्रिया को सहयोग देने के लिए एक उपखंड भी बनाया गया है, जो ऐसी परियोजनाओं को आर्थिक और दक्षता निर्माण में सहयोग करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनः खोज और उसे शोध एवं शिक्षण से जोड़ने की इस परियोजना की एक बड़ी समस्या इसके अर्थ का गलत पाठ और अनेक वृत्तांतात्मक उलझावों एवं अफवाहपूर्ण अवधारणाओं से गुजरना है। इस संदर्भ में पहले चुनौती इसके अर्थ एवं तत्व मीमांसा की है। भारतीय ज्ञान परंपरा वस्तुतः भारतीय समाज और उसके मिट्टी-पानी और सांस्कृतिक पर्यावरण से उभरा ज्ञान है। यह किसी एक जाति, पंथ और संस्कृति में सृजित एवं विकसित हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि यह उन सभी घटकों के सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव का ज्ञान समुच्चय है, जिनसे भारतीय समाज बनता है।

यह बहुलतावादी सामाजिक संस्कृति से उभरा ज्ञान है। यह भारतीय जमीन और पर्यावरण में पले-बढ़े हर संस्कृति के अनुभवों से उभरा ज्ञान है। अतः इसे किसी एक जाति, पंथ और संस्कृति में सीमित करना इसके तात्विक अर्थ का गलत पाठ करना है। हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसी कोटियां से परे यह हर

समुदाय, समाज एवं संस्कृति के लौकिक एवं दार्शनिक ज्ञान पर शोध-अध्ययन की हमें छूट देता है। एक तरफ वाल्मीकि, भरतमुनि, वेदव्यास, चरक, सुश्रुत, पतंजलि, कौटिल्य का ज्ञान लोक भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा है, दूसरी तरफ बुद्ध, नागार्जुन, भर्तृहरि, कबीर, नानक, रविदास के आख्यान इस ज्ञान विमर्श को रचते हैं। साथ ही अमीर खुसरो, दारा शिकोह तथा अन्य सूफियों का ज्ञान एवं योगियों का विमर्श भी इसमें शामिल है। तात्पर्य यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में सीमांत पर बसे समुदायों, दलित, वंचित, शिकोह तथा अन्य सूफियों का ज्ञान एवं योगियों का विमर्श भी इसमें शामिल है। भारतीय ज्ञान परंपरा का परिप्रेक्ष्य समाज की हर सामाजिक इकाई को एक सांस्कृतिक इकाई मानता है, जो अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों के बीच सांस्कृतिक, समर्थितक और आध्यात्मिक ज्ञान सृजित करता है। भारत में हर सामाजिक इकाई का एक लोक-जीवन होता है, जिसके अपने गीत, संगीत, सबद, भजन, कीर्तन, कव्वाली, मुहावरे, मसले होते हैं, जिनमें उन सामाजिक समूहों का ज्ञान, विवेक, तकनीकी, दक्षता और नीतियां भरी होती

फरक्का समझौते से न हो देश को क्षति

संजय कुमार झा

फरक्का जल संधि के पिछले तीन दशकों के अनुभव और आंकड़े ठोस प्रमाण हैं कि बिहार को इससे बाढ़ और सुखाड़ की दोहरी मार झेलनी पड़ी है। सितंबर 199६ में तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार के विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल (जो बाद में प्रधानमंत्री बने) द्वारा प्रतिपादित ‘गुजराल डॉक्ट्रिन’ का मूल मंत्र था कि भारत को बड़ा दिल दिखाते हुए पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में ‘एकतरफा रियायत’ देनी चाहिए। विव्दबना यह रही कि इस नीति के तहत दिसंबर 199६ में बांग्लादेश को जल-अधिकार सौंपते वक़्त जब बिहार के हितों की बलि चढ़ाई जा रही थी, तब मुख्यमंत्री लालू यादव मौन साधे रहे, जो संयुक्त मोर्चा के एक प्रभावी नेता थे। केंद्र सरकार को बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी भी मूल रूप से बिहार के ही थे। यदि उसी समय संधि का विरोध हुआ होता, तो बिहार को बीते तीन दशकों में हुआ भारी नुक़सान नहीं झेलना पड़ता। अब जबकि फरक्का जल संधि की 30 वर्षों की समयसीमा दिसंबर 202६ में समाप्त होने जा रही है, तब यह प्रश्न केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि व्यापक जनहित और जल-सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्रहित से जुड़ा

कश्मीर पर अमेरिका का बदलता रुख

प्रमोद भार्गव

जिसे अक्सर ‘भारतीय प्रशासन वाले कश्मीर’ जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता रहा है। ऐसे में कश्मीर की धरती पर एक वर्षित अमेरिकी राजनयिक का यह दो दृक बनाना इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर कश्मीर को लेकर भारत की अखंडता एवं संप्रभुता की पुष्टि के रूप में देखा जा रहा है। इस बयान से पाकिस्तान को तो झटका लगा ही है, चीन भी सकते में है। अमेरिका ने वर्ष 2018 से ही जम्मू-कश्मीर के तात्कालिक पूर्वी लद्दाख और लेह को छोड़कर अपने नागरिकों को यात्रा नहीं करने की चेतावनी दी हुई है। इस यात्रा चेतावनी को चौथी श्रेणी में रखा हुआ है। गौर ने फिलहाल इस यात्रा चेतावनी को कम करने का कोई संकेत नहीं दिया है लेकिन उम्मीद है कि इस बिंदु पर अमेरिका यात्रा में छूट दे सकता है। हालाँकि उस समय अनुच्छेद-370 बहाल थी और घाटी में आतंकी संघट की छाया छाई रहती थी। अगस्त 2019 में अनुच्छेद-370 और 35-ए को भारत सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते विलोपित कर दिया, उसी के बाद से कश्मीर में सुरक्षा संबंधी हालातों में निरंतर सुधार हो रहे हैं और पत्थरबाजी व अन्य आतंकी घटनाओं में कमी आई है। पहलगाम में आतंकी हमले के एक दिन बाद ही अमेरिकी विदेश

थी। पाकिस्तान धर्म की घुड़ि पिलाकर 35 साल से भारत पर आतंकी हमले करता रहा है। जबकि उसे सबसे मुकम्मल जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया था लेकिन वह बाज नहीं आ रहा है। गैर-कश्मीरियों और हिंदुओं की हत्या के लिए उसकी क़त्ला समाप्त नहीं हो रही है। जाहिर है, पाकिस्तान भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बदले को भूल गया है। उसे एक बार फिर कराग जबाब देना होगा। दरअसल, इस समय पाकिस्तान अपने कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में चल रहे आजादी के आंदोलन से भी जूझ रहा है। वहां भी उसने निर्ममता बरतते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को भूतने का काम किया है। पाक की ये हकतें इसलिए भी बरकरार हैं क्योंकि ईरान हमले में उलझा अमेरिका उसकी पीठ थपथपाने में लगा है। ऐसे में भारत को अनेक कूटनीतिक कदम उठकर पाकिस्तान को विवश करना पड़ रहा है। अब जाकर उसे कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका का दो टूक जवाब मिला है। अनुच्छेद-370 हटने के बाद भी हालातों में सुधार नहीं हो पा रहा है तो इसका एक बड़ा कारण मजहबी कट्टरता पर चोट नहीं कर पाना है। साफ है कि यह समस्या अब राजनैतिक व संवैधानिक नहीं रह गई है बल्कि धार्मिक चरमपंथ के रूप में सामने आ रही है। इस हिसक उन्माद का सोच पाकिस्तान से निर्यात आतंकवाद तो है ही, घाटी में कुकुमुतों की तरह मस्जिदों और

मदरसों में फैला, वह शिक्षा का तंत्र भी है, जो आतंक की फसल बोने और उगाने का काम करता है। यही वजह है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं, उनमें न तो अल्पसंख्यकों का जनसंख्यात्मक घनत्व बढ़ रहा है और न ही उन्हें नागरिक समानता के अधिकार मिल रहे हैं। कश्मीर में भी जिहादी चाहते हैं कि गैर-मुस्लिम या तो इस्लाम स्वीकार करें या फिर घाटी छोड़ जाएं। इस दोषपूर्ण मंश को संविधान निर्माण के समय ही डॉ. भीमराव अंबेडकर ने समझ लिया था। शेख अब्दुल्ला ने जब जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने की मांग की तो अंबेडकर ने सख्त लहजे में कहा था कि ‘आप चाहते हो कि भारत कश्मीर की रक्षा करे, कश्मीरियों की आर्थिक सुरक्षा करे, कश्मीरियों को संपूर्ण भारत में समानता का अधिकार मिले लेकिन भारत और अन्य भारतीयों को आप कश्मीर में कोई अधिकार देना नहीं चाहते? में देश का कानून मंत्री हूं और मैं अपने देश के साथ कोई अन्याय का संकट देश बंटवारे से लेकर अबतक भुगत रहा है। यही वजह है कि इस बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो हिंदू, बौद्ध, सिख और दलित आतंकियों के रूप में जम्मू-कश्मीर में ही उठ गए थे, उन्हें मौलिक अधिकार अनुच्छेद-370 हटने

के बाद मिल पाए हैं। इनकी संख्या करीब 70-80 लाख है, ये 5६ शरणार्थी शिविरों में सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से महकम रहते हुए बद से बदतर जिंदगी का अभिशाप अनुच्छेद-370 हटने से पहले तक भोगते रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद जितने भी आतंकी हमले कश्मीर में हुए हैं, उनमें से ज्यादातर की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली थी। यह लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मुजौदा संगठन है। यह लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों की आतंकी हरकतों को अजाम देता है। भारतीय सेना ने कोटली अब्बास में जिस आतंकी शिविरों को तबाह किया किया था, इसमें 1500 आतंकियों को प्रशिक्षण दिया गया था। मुरोके में बिहार की सिंघाई, पेयाल और औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाएं प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

जलाशय से समृद्धि की राह: मोरगा की आदर्श मछुआ सहकारी समिति ने 25 परिवारों को दिया रोजगार और आत्मनिर्भरता का आधार

80 हजार के निवेश से 2.80 लाख का लाभ: मोरगा की मछुआ सहकारी समिति ने लिखी आत्मनिर्भरता की नई इबारत



मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। जब प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग सामूहिक प्रयास तकनीकी मार्गदर्शन और वैज्ञानिक सोच के साथ किया जाए, तो वही संसाधन ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और नियमित आय का मजबूत आधार बन सकते हैं मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के ग्राम मोरगा की आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्यादित मोरगा की कार्य नहीं, बल्कि रोजगार, अतिरिक्त आय और आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है जलाशय के संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग, 25 सदस्यों को मिला रोजगार का आधार आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्यादित मोरगा का पंजीयन 5 जून 2018 को हुआ था समिति का मुख्य उद्देश्य जलाशय में उपलब्ध मत्स्य संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए अपने सदस्यों को रोजगार एवं नियमित आय का साधन उपलब्ध कराना रहा है समिति द्वारा लाभग 11 हेक्टेयर जलक्षेत्र वही जलाशय में सामूहिक रूप से मत्स्य पालन एवं मत्स्याखेट

किया जाता है समिति के सदस्यों ने जल संसाधन को केवल पारंपरिक तरीके से उपयोग करने के बजाय इसे संगठित आर्थिक गतिविधि में बदलने का प्रयास किया मत्स्य विभाग के अधिकारियों से प्राप्त तकनीकी मार्गदर्शन के आधार पर जलाशय प्रबंधन, मत्स्य बीज संचयन, मछलियों की देखभाल, हार्वेस्टिंग और विपणन की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया गया। इससे सदस्यों को मत्स्य पालन के साथ उत्पादन, प्रबंधन और बाजार से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी भी प्राप्त हुई 80 हजार रुपये के निवेश से बढ़ी उत्पादन क्षमता, 3.50 लाख का वार्षिक करोबार समिति ने पिछले वर्ष लगभग 80 हजार रुपये की लागत से मत्स्य बीज का संचयन किया विभागीय अधिकारियों के तकनीकी मार्गदर्शन में जलाशय में गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज खले गए और जलाशय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। मछलियों के उचित आकार और वजन तक पहुंचने के बाद समिति के सदस्य सामूहिक रूप से उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके बाद मछलियों को

सदस्यों को मत्स्य बीज संचयन, जलाशय प्रबंधन, मत्स्याखेट, मछलियों की हैडलिंग, संरक्षण और विपणन से संबंधित तकनीकी जानकारी दी जाती है। इससे समिति के कार्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बेहतर प्रबंधन विकसित हुआ है कृषि के साथ मत्स्य पालन बना अतिरिक्त आय का मजबूत जरिया मत्स्य गतिविधियों से जुड़ने के बाद समिति के सदस्यों के लिए रोजगार और आय का एक नया स्रोत विकसित हुआ है पहले सदस्यों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि और स्थानीय स्तर के अन्य कार्यों पर निर्भर थी। मत्स्य पालन को अतिरिक्त गतिविधि के रूप में



पिछले साल से 16.68 इंच कम बारिश, तवा डैम 54' खाली मृंगा की सिंचाई पर मंडरा रहा संकट



मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में इस मानसून अब तक अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है। रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते 20 अगस्त तक जिले में करीब 22.47 इंच बारिशदर्ज की गई है यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 16.68 इंच कम है। कम बारिश का असर जिले के प्रमुख तवा डैम के जलस्तर पर भी दिखाई दे रहा है डैम फिलहाल करीब 46 फीसदी भरा है और 54 फीसदी खाली है सिंचाई विभाग के ईई अंकित सराफ के अनुसार तवा डैम का वर्तमान जलस्तर 1144 फीट है बैतूल और पचमढ़ी क्षेत्र से धीरे-धीरे पानी की आवक हो रही है मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए डैम के 70 से 75 फीसदी तक भरने का अनुमान है यदि डैम पूरी क्षमता तक नहीं भर पाया तो अगले साल गर्मी में मृंगा फसल की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में परेशानी हो सकती है इसका सीधा असर नर्मदापुरम और हरदा जिले के किसानों पर पड़ सकता है पचमढ़ी में सबसे ज्यादा, माखननगर में सबसे कम बारिश जिले में अब तक सबसे अधिक 844 मिमी बारिश पचमढ़ी में दर्ज हुई है जबकि माखननगर में 352 मिमी बारिश हुई है। इसके अलावा सिवनी मालवा में 539 मिमी, इटारसी में 572 मिमी, सोहागपुर में 549 मिमी, पिपरिया में 553.6 मिमी, बनखेड़ी में 564.8 मिमी और डोलरिया में 481.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है मौसम विभाग ने जिले में 21 और 22 अगस्त को बारिश होने की संभावना जताई है हालांकि गुरुवार सुबह मौसम साफ रहा और धूप खिली रही किसानों और सिंचाई विभाग की नजर अब आगामी बारिश पर टिकी ह प्रमुख जलस्तर: सेठनी घाट 938.9 फीट, तवा डैम 1144 फीट, बरगी डैम 1382.8 फीट और बारना डैम 1138 फीट।

नर्मदापुरम में 5 कॉलोनियों में एक घंटे बिजली कटौती नए सब-स्टेशन से 20 से ज्यादा कॉलोनियों को मिलेगी राहत

मीडिया ऑडिटर,नर्मदापुरम (निप्र)। शहर में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मालाखेड़ी क्षेत्र में बनाए जा रहे नए 33/11 केवी सब-स्टेशन का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। सब-स्टेशन शुरू होने के बाद मालाखेड़ी, चक्कर रोड, नर्मदा टाउन और आसपास की 20 से अधिक कॉलोनियों में बार-बार होने वाली बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है नए सब-स्टेशन से लाइन जोड़ने का कार्य गुरुवार को भी जारी रहेगा। इसके चलते नर्मदा टाउन फीडर सुबह 10 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगा। बिजली कंपनी के अनुसार इस दौरान गोकुलधाम, साईंछत्र, रिशिपुरम, क्रिशन रेसीडेंसी, वैदिक विहार, आईबीडी नेचुरल



परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी अधिक लोड के कारण आती थी समस्या मालाखेड़ी रोड, नर्मदा टाउन, हाउसिंग बोर्ड और चक्कर रोड क्षेत्र में लंबे समय से बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की शिकायतें सामने आती रही हैं। मौजूदा फीडरों पर

अधिक लोड होने के कारण गर्मी और बारिश के मौसम में समस्या बढ़ जाती थी। वहीं लाइन में खराबी या रखरखाव के दौरान कई क्षेत्रों में घंटों बिजली बंद रहने की स्थिति बिजली की इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए बिजली कंपनी ने मालाखेड़ी में नया 33/11 केवी

सब-स्टेशन तैयार कराया है। इससे बिजली आपूर्ति का लोड विभाजित होगा और संबंधित क्षेत्रों में सप्लाई व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है जल्द शुरू होगी सप्लाई बिजली कंपनी के जोन-2 के आई राहुल कुमार ने बताया कि सब-स्टेशन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है नई लाइन जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है लाइन का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है जल्द ही टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर सब-स्टेशन से बिजली सप्लाई शुरू कर दी जाएगी नए सब-स्टेशन के चालू होने के बाद मालाखेड़ी और आसपास की 20 से अधिक कॉलोनियों के उपभोक्ताओं को बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।

इटारसी में कांग्रेस की संगठन सृजन अभियान बैठक: बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर, 80 लोगों ने ली सदस्यता

मीडिया ऑडिटर, नर्मदापुरम (निप्र)। इटारसी स्थित जिला कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को संगठन सृजन अभियान के तहत जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई बैठक में मध्यप्रदेश कांग्रेस की प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव उषा नायडू ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण से शुरुआत कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपान के साथ हुई इसके बाद प्रदेश प्रभारी उषा नायडू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डुन पाण्डेय और नगर अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों और जमीनी स्तर पर पार्टी की सक्रियता को लेकर चर्चा की गई संगठन की मजबूती को बताया पार्टी की ताकत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उषा नायडू ने कहा कि संगठन की मजबूती ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है प्रहोंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आपसी



समन्वय के साथ काम करने तथा आम लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की बात कही उन्होंने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए आंदोलनों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डुन पाण्डेय ने प्रदेश प्रभारी के समक्ष जिले में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर किए गए आंदोलनों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की उन्होंने संगठन को मौजूदा गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की

जानकारी भी दी 80 नए कार्यकर्ताओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता बैठक के दौरान सोहागपुर और नर्मदापुरम क्षेत्र से आए करीब 80 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की जिला अध्यक्ष गुड्डुन पाण्डेय ने नए सदस्यों का कांग्रेस का गमछ पहनाकर स्वागत किया इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और पार्टी की गतिविधियों को गांव एवं बूथ स्तर तक पहुंचाने का संकल्प लिया बैठक में कांग्रेस के जिला एवं स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक मौजूद रहे।

एमसीबी जिले में अब तक 819.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज, कोटाडोल में सबसे अधिक बारिश

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी है। 1 जून से 20 अगस्त 2026 तक मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में कुल 819.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है जिला प्रशासन के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले की विभिन्न तहसीलों में वर्षा की स्थिति में अंतर देखने को मिला है जारी आंकड़ों के मुताबिक कोटाडोल तहसील में सबसे अधिक 952.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है वहीं खड़गावा तहसील में सबसे कम 615.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ तहसील में 923.2 मिलीमीटर, चिरमिरी में 852.1 मिलीमीटर तथा केलहारी तहसील में 647.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है इसी क्रम में भरतपुर तहसील में अब तक 924.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है तहसीलवार आंकड़ों से स्पष्ट है कि कोटाडोल और भरतपुर क्षेत्र

में इस मानसून अपेक्षाकृत अधिक बारिश हुई है जबकि खड़गावां और केलहारी में वर्षा का आंकड़ा अन्य तहसीलों की तुलना में कम रहा है बारिश के चलते जिले के ग्रामीण और बर्नांचल क्षेत्रों में जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है लगातार हो रही वर्षा से नदी-नालों में पानी का प्रवाह भी बढ़ा है प्रशासन द्वारा मौसम एवं वर्षा की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है जिला प्रशासन के अनुसार आगामी दिनों में मौसम की स्थिति को देखते हुए तहसील स्तर पर वर्षा संबंधी आंकड़ों का संकलन और निगरानी जारी रहेगी बारिश के आंकड़ों के आधार पर किसानों और आम नागरिकों को मौसम की परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक सावधानी बरतने का सलाह दी जा रही है तहसीलवार वर्षा मनेन्द्रगढ़ 923.2 मिमी, चिरमिरी 852.1 मिमी, केलहारी 647.0 मिमी, भरतपुर 924.5 मिमी, कोटाडोल 952.9 मिमी और खड़गावां 615.9 मिमी।

डिजिटल दुनिया में बेटियों की सुरक्षा पर जोर: नौगई स्कूल में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम संपन्न, छात्राओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के बताए महत्वपूर्ण उपाय

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौगई में बालिकाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में छात्राओं को इंटरनेट और सोशल मीडिया के बड़ो उपयोग के बीच ऑनलाइन सुरक्षा, निजी जानकारी की गोपनीयता, मजबूत पासवर्ड, संदिग्ध लिंक और साइबर अपशर्षों से बचाव के महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी दी गई कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को डिजिटल दुनिया का सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग करने के लिए जागरूक एवं सक्षम बनाना रहा कार्यक्रम कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े के निदेशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में



आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन महिला सशक्तिकरण केंद्र हब की जिला मिशन समन्वयक श्रीमती ताग कुशवाहा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं को साइबर सुरक्षा से जुड़ी व्यवहारिक जानकारीयें सरल भाषा में समझाई गई ताकि वे इंटरनेट का उपयोग करते समय संपावित जोखिमों को पहचान सकें और किसी भी साइबर धोखाधड़ी अथवा ऑनलाइन उर्पीड़न की स्थिति में सतर्कता बस

सकें निजी जानकारी साझा करने से बचने की दी सीख कार्यक्रम में बालिकाओं को विषय रूप से समझाया गया कि इंटरनेट की दुनिया में अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है उन्हें बताया गया कि अपना पूरा नाम, घर का पता, स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ओटीपी, बैंक संबंधी जानकारी अथवा अन्य निजी विवरण किसी अनजान व्यक्ति के साथ ऑनलाइन साझा नहीं करना चाहिए

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों से आने वाले प्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड्स अथवा चैट का जवाब देने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी गई बालिकाओं की बताया गया कि साइबर अपशर्ष कई बार परिचित व्यक्ति बनकर या आकर्षक ऑफर, इनाम, नौकरी अथवा अन्य प्रलोभन देकर व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे किसी भी संशय या अनुरोध पर तुरंत विश्वास करने के बजाय पहले उसकी सत्यता की जांच करना आवश्यक है मजबूत पासवर्ड और संदिग्ध लिंक से सावधानी कार्यक्रम में छात्राओं को मजबूत पासवर्ड बनाने के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसका अनुमान आसानी से न लगाया जा सके।

मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए डैम के 70 से 75 फीसदी तक भरने का अनुमान है यदि डैम पूरी क्षमता तक नहीं भर पाया तो अगले साल गर्मी में मृंगा फसल की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में परेशानी हो सकती है इसका सीधा असर नर्मदापुरम और हरदा जिले के किसानों पर पड़ सकता है पचमढ़ी में सबसे ज्यादा, माखननगर में सबसे कम बारिश जिले में अब तक सबसे अधिक 844 मिमी बारिश पचमढ़ी में दर्ज हुई है जबकि माखननगर में 352 मिमी बारिश हुई है। इसके अलावा सिवनी मालवा में 539 मिमी, इटारसी में 572 मिमी, सोहागपुर में 549 मिमी, पिपरिया में 553.6 मिमी, बनखेड़ी में 564.8 मिमी और डोलरिया में 481.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है मौसम विभाग ने जिले में 21 और 22 अगस्त को बारिश होने की संभावना जताई है हालांकि गुरुवार सुबह मौसम साफ रहा और धूप खिली रही किसानों और सिंचाई विभाग की नजर अब आगामी बारिश पर टिकी ह प्रमुख जलस्तर: सेठनी घाट 938.9 फीट, तवा डैम 1144 फीट, बरगी डैम 1382.8 फीट और बारना डैम 1138 फीट।

शराब के नशे में बेटे ने पिता से की मारपीट: लाठियों से हमला, घायल पिता जिला अस्पताल में भर्ती

मीडिया ऑडिटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले के बैरगढ़ थाना क्षेत्र के ऊंवी खर्ई गांव में गुरुवार रात पारिवारिक विवाद के दौरान एक युवक ने अपने 55 वर्षीय पिता के साथ मारपीट कर दी आरोप है कि युवक शराब के नशे में था और उसने लाठियों से पिता पर हमला किया घटना में घायल पिता को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है पीड़ित ब्रजमोहन जाटव (55), पिता प्रभु जाटव ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा विककी (28) शराब का आदी है उनके अनुसार बेटे के कुछ दोस्त उसे यह कहकर भड़काते हैं कि पिता उसके साथ भेदभाव करते हैं और परिवार के अन्य बेटों का पक्ष लेते हैं ब्रजमोहन के मुताबिक गुरुवार रात विककी शराब

के नशे में घर पहुंचा। इसी दौरान उसने पिता से विवाद शुरू कर दिया। विवाद बढ़ते पर विककी ने लाठियों से उनके साथ मारपीट कर दी। हमले में ब्रजमोहन घायल हो गए। परिसर और आसपास के लोगों की मदद से उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है घायल पिता ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में कच्ची शराब की कथित बिक्री को लेकर भी चिंता जताई उनका आरोप है कि खडबपुर की कंजर बस्ती में कुछ लोग कच्ची शराब तैयार करते हैं उनका कहना है कि आसानी से शराब उपलब्ध होने के कारण गांव के कई युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं ब्रजमोहन ने प्रशासन और पुलिस से अवैध शराब की बिक्री पर कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके।

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निराकरण पर जोर

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। विद्युत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, उपलब्ध सेवाओं तथा शिकायत निवारण व्यवस्था के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा 19 अगस्त 2026 को ईई संचार-संधारण संभाग मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में फोरम के अध्यक्ष डी.के. सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कार्यशाला में मनेन्द्रगढ़ संचार-संधारण संभाग के कार्यपालन अभियंता एस.के. खाखा सहित सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं विद्युत

उपभोक्ता उपस्थित रहे समस्या का समय पर निराकरण नहीं होने पर फोरम में शिकायत फोरम के अध्यक्ष डी.के. सैनी ने उपभोक्ताओं को शिकायत निवारण की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि बिजली बिल में त्रुटि, मोटर रीडिंग में गड़बड़ी, विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्या तथा अन्य विद्युत सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का विभागीय स्तर पर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर उपभोक्ता विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं उन्होंने बताया कि फोरम द्वारा शिकायतों की सुनवाई कर नियमानुसार उनका निराकरण किया जाता है।



मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। संपावित बाढ़ आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियों, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को परखने के उद्देश्य से तहसील नागपुर अंतर्गत हसदेव नदी डैमकेल एवं ग्राम पंचायत लाई स्थित नवी विभाग नर्सरी परिसर में बाढ़ आपदा मॉकड्रिल का सफल आयोजन किया गया।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभ्यास में बाढ़ की काल्पनिक स्थिति निर्मित कर राहत एवं बचाव कार्यों की पूरी प्रक्रिया को मौके पर जीवंत रूप से प्रदर्शित किया गया मॉकड्रिल में एसडीआरएफ की टीमों ने संयुक्त रूप से नदी के टापू में फंसे विभाग नर्सरी परिसर में बाढ़ आपदा मॉकड्रिल का सफल आयोजन किया गया।

मोटर बोट, रेस्क्यू रिसियों एवं अन्य आधुनिक उपकरणों की सहायता से सुरक्षित निकालने का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ढहे मकान में दबे लोगों के रेस्क्यू और सर्पदर्श पीड़ित को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया गया बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के लिए 18 अगस्त 2026 को Table Top E&ercise (ITEX) आयोजित की गई थी इसके बाद मैदानी मौक एक्सरसाइज के माध्यम से प्रशासन एवं विभिन्न विभागों की वास्तविक समय में प्रतिक्रिया क्षमता, उपलब्ध संसाधनों, आपसी समन्वय, राहत-बचाव व्यवस्था और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण किया गया अभ्यास में बाढ़ की सूचना मिलने से लेकर सूचना तंत्र सक्रिय करने, ईसिडेंट कमांडर ग्रामीणों, तेज बहाव में डूबते व्यक्तियों, पेड़ों की डालियों और पुल पर फंसे लोगों को

पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को परखा गया। एसडीएम लिंगराज सिदार को ईसिडेंट कमांडर, डिटी कलेक्टर विजयेंद्र सारथी एवं शशि शेखर मिश्रा को सहायक ईसिडेंट कमांडर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था मॉकड्रिल की शुरुआत हसदेव नदी के टापू में बाढ़ के पानी के बीच फंसे ग्रामीणों के रेस्क्यू से हुई। प्रशिक्षण बचाव दल मोटर बोट एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ फंसे लोगों तक पहुंचे और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला इसके बाद तेज बहाव में डूबते व्यक्तियों को बचाने का अभ्यास किया गया। रेस्क्यू टीम ने लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, रेस्क्यू रिसियों और मोटर बोट की मदद से प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने की तकनीक प्रदर्शित की। पेड़ों की डालियों और पुल पर फंसे लोगों को निकालने की कार्रवाई का भी जीवंत प्रदर्शन किया गया

बाढ़ से ढहे मकान में दबे लोगों को निकालने तथा सर्पदर्श पीड़ित को प्राथमिक उपचार उपलब्ध करार अस्पताल तक पहुंचाने की प्रक्रिया ने यह भी परखा कि एक साथ उत्पन्न होने वाली विभिन्न आपदा परिस्थितियों में राहत एवं बचाव दल कितनी तेजी और समन्वय के साथ कार्रवाई कर सकते हैं एसडीआरएफ की टीमों ने मॉक ड्रिल के दौरान आधुनिक बचाव तकनीकों और उपकरणों का प्रदर्शन किया मोटर बोट, स्कूबा डाइविंग उपकरण, अंडरवाटर कैमरा, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, पेलिकन लाइट, सच लाइट और फायर ब्रिगेड सहित विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया गया खोरों ने नदी के गहरे पानी में डूबे या लापता व्यक्तियों की तलाश और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की तकनीक दिखाई अंडरवाटर कैमरे के माध्यम से पानी के भीतर खोज अभियान की प्रक्रिया भी प्रदर्शित की गई।

सिवनी में मानसून सक्रिय, 623 मिमी वर्षा दर्ज

1 जून से अब तक 623 मिमी पानी गिरा; नदी-नाले उफान पर

मीडिया ऑडीटर, सिवनी (निप्र)। सिवनी जिले में लगभग दो सप्ताह के अंतराल के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बुधवार रात से शुरू हुआ बारिश का दौर गुरुवार को भी जारी रहा, जिससे जिले में 1 जून से अब तक 623.0 मिमी औसत संचयी वर्षा दर्ज की गई है। प्रशासन ने नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सिवनी मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार रात से ही बारिश शुरू हो गई थी, जो गुरुवार को भी जारी रही। दिनभर रुक-रुककर रिमझिम बारिश होती रही और गुरुवार सुबह से भी आसमान में बादल छाए रहे। इस बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है, वहीं मौसम में ठंडक घुल गई है।

लगातार बारिश के कारण दैनिक कामकाज के लिए घर से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर सड़कें गीली होने से पैदल



चलने वालों को आवागमन में दिक्कत हुई। जिले की नदियों, नालों, तालाबों और अन्य जलस्रोतों के जलस्तर में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने

की अपील की है। निर्देश दिए गए हैं कि यदि नदी, नाले, पुल या पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा हो तो उसे पार करने का प्रयास न करें। बारिश के दौरान बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए खुले

स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से भी बचने की सलाह दी गई है। जिले में 1 जून से अब तक कुल 623.0 मिमी औसत संचयी वर्षा दर्ज की गई है। तहसीलवार आंकड़ों के अनुसार, सिवनी में 711.0 मिमी, बरघाट में 698.2 मिमी, लखनादौन में 715.7 मिमी, केवलारी में 615.4 मिमी, कुरई में 513.6 मिमी, धनौरा में 612.0 मिमी, छपारा में 93.8 मिमी और घंसौर में 584.2 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हाल की अवधि में जिले में 1.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस बारिश से खरीफ फसलों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। धान, मक्का, सोयाबीन सहित अन्य फसलों के लिए पर्याप्त नमी मिलने से किसानों को फायदा होगा। हालांकि, लगातार तेज बारिश होने पर खेतों में जलभराव की स्थिति बनने से फसलों पर प्रतिकूल असर भी पड़ सकता है, इसलिए किसानों को जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी गई है।

पिपरिया में दस दिन बाद बारिश, धान को फायदा

पिछले साल के मुकाबले 22 इंच कम बरसा पानी लोगों को उमस से मिली निजात



मीडिया ऑडीटर, पिपरिया (निप्र)। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया और आसपास के इलाकों में गुरुवार दोपहर 10 दिन के लंबे इंतजार के बाद तेज बारिश हुई। दोपहर करीब 2 बजे बादलों की गरज के साथ शुरू हुई आधे घंटे की तेज वर्षा और उसके बाद हुई बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया। इस बारिश से सूख रही धान की फसलों को नया जीवन मिलने

की उम्मीद जगी है।

30 मिनट की बारिश से पानी-पानी हुई सड़कें: गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा था। दोपहर में आधे घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के चलते नगर के मुख्य मार्गों और निचले इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया। इस बारिश से लोगों को लंबे समय से सता रही गर्मी और उमस से काफी हद तक राहत मिली।

पिछले साल के मुकाबले 22 इंच कम बरसा पानी: मौसम केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, क्षेत्र में अब तक कुल 21.77 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि बीते वर्ष इसी अवधि तक 43.58 इंच वर्षा हो चुकी थी। इस तरह इस सीजन में अब तक पिछले साल की तुलना में लगभग 22 इंच कम बारिश हुई है।

किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान इससे पहले क्षेत्र में 10 अगस्त को 73 मिमी बारिश हुई थी, जिसके बाद से केवल हल्की फुहारें ही पड़ी थीं। लंबे समय से बारिश न होने के कारण धान की फसल के प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई थी, जिससे किसान चिंतित थे। गुरुवार को हुई इस बारिश ने धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई है।

रायसेन में 8 दिन से बारिश नहीं:पिछले साल से 19.51 इंच कम पानी, बांध-तालाब आधे-अधूरे गेट खोलने की नौबत नहीं



मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले में पिछले आठ दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिससे नदी-नाले फिर से खाली हो गए हैं। इस साल 19 अगस्त तक जिले में औसत 654.63 मिलीमीटर (25.77 इंच) बारिश दर्ज की गई है। यह पिछले साल की इसी अवधि में हुई 1150 मिलीमीटर (45.28 इंच) बारिश से 495 मिलीमीटर (19.51 इंच) कम है। अगस्त माह में अब तक औसत बारिश की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत ही वर्षा हुई है। कम बारिश के कारण जिले के बांध और तालाब अपनी क्षमता से नहीं भर पाए

हैं। इस सीजन में जलाशयों के गेट एक बार भी नहीं खोले गए हैं। पिछले दिनों हुई तेज बारिश से नदी-नालों में पानी आया था, लेकिन बारिश का दौर थमने के बाद जलस्तर फिर से नीचे जाने लगा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए रायसेन में भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। जिले में वर्षाकाल की सामान्य औसत बारिश 1197.1 मिलीमीटर (47.13 इंच) मानी जाती है। ऐसे में किसानों और जलस्रोतों को अब एक और अच्छी बारिश का इंतजार है।

जानिए जिले में कहां कितनी बारिश हो चुकी: रायसेन में 579.8 मिमी (22.83 इंच), गैरतगंज में 775.8 मिमी (30.54 इंच), बेगमगंज में 782.1 मिमी (30.79 इंच), सिलवानी में 505 मिमी (19.88 इंच), गौहरगंज में 595.7 मिमी (23.45 इंच), बरेली में 492.2 मिमी (19.38 इंच), उदयपुरा में 844 मिमी (33.23 इंच), बाड़ी में 627 मिमी (24.69 इंच), सुल्तानपुर में 686.8 मिमी (27.04 इंच) और देवरी में 657.9 मिमी (25.90 इंच) बारिश दर्ज की गई है।

एग्रीस्टैक अभियान के तहत पात्र कृषकों की शत-प्रतिशत फार्मर आईडी बनाने पर जोर 20 अगस्त से 15 सितम्बर तक चलेगा प्रदेशव्यापी अभियान

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। रबी वर्ष 2026-27 में किसानों को उर्वरकों की आवश्यकता के अनुरूप समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने, ई-विकास प्रणाली के माध्यम से उर्वरक टोकन सहित पोर्टल की विभिन्न सुविधाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने तथा अधिकाधिक किसानों को पैक्स की सदस्यता दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश में ‘एग्रीस्टैक पंजीयन, पैक्स सदस्यता एवं अग्रिम उर्वरक उठाव अभियान’ आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान 20 अगस्त से 15 सितम्बर 2026 तक चलेगा। अभियान के दौरान पात्र कृषकों की फार्मर आईडी बनाने, लिंबित बकेटिंग प्रकरणों का निराकरण करने, पैक्स में अधिकाधिक किसानों को सदस्य बनाने तथा केसीसी सेचुरेशन के लक्ष्य को पूरा करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर होगा अभियान का प्रभावी क्रिया-व्ययन: अभियान के तहत राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ग्राम

पंचायत स्तरीय कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता की जाएगी। ऐसे भूमिस्वामी जिनके खातों में हिस्सा निर्धारित नहीं है, उनके प्रकरणों में पटवारी स्तर पर परिमार्जन की गतिविधि प्रारंभ कर तहसीलदार स्तर से अनुमोदन कराया जाएगा, ताकि संबंधित किसान अपनी भूमि को फार्मर आईडी से जोड़ सकें। सारा पोर्टल पर उपलब्ध डैशबोर्ड एवं रिपोर्ट के माध्यम से लिंबित भूमिस्वामियों की सूची प्राप्त कर ऐसे किसानों की ग्रामवार सूची तैयार की जाएगी, जिनकी फार्मर आईडी अभी नहीं बनी है। यह सूची ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे माध्यम से लिंबित भूमिस्वामियों की पहचान कर उनका पंजीयन मिशन मोड में पूरा कराया जा सके। जिन किसानों की फार्मर आईडी पहले से बन चुकी है, लेकिन उनके सभी सर्वे नंबर आईडी से लिंक नहीं हैं, उनके शेष सर्वे नंबर खंडूइंद्रहर छद्महड्डूइंद्रधब्ध क्षसड्डूइंद्र विकल्प के माध्यम से जोड़े जाएंगे। साथ ही, यदि किसी किसान की फार्मर आईडी में गलती से किसी अन्य किसान की भूमि जुड़ गई

है, तो संबंधित रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन कर उसे दुरुस्त किया जाएगा।

किसानों को फार्मर आईडी के महत्व की दी जाएगी जानकारी: अभियान के दौरान किसानों को फार्मर आईडी की उपयोगिता के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। किसानों को बताया जाएगा कि फार्मर आईडी विभिन्न कृषि योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को गेहूं, चना, सरसों, धान, मूंग आदि फसलों के उपार्जन, उर्वरक प्राप्ति, फसल पर बीज प्राप्त करने, फसल प्रदर्शन, कृषि यंत्रों पर अनुदान तथा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने और ई-मंडी के माध्यम से कृषि उपज विक्रय के लिए भी फार्मर आईडी महत्वपूर्ण है।

विदिशा जिले में अब तक 47.81 प्रतिशत कार्य पूर्ण: 18 अगस्त 2026 की स्थिति में विदिशा जिले में 47.81

प्रतिशत पात्र कृषकों की फार्मर आईडी बनाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अभियान के तहत शेष पात्र कृषकों का पंजीयन प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। जिले में तहसीलवार एवं ग्रामवार प्रगति की लगातार समीक्षा करते हुए जिन कृषकों अथवा भूमिस्वामियों की फार्मर आईडी लिंबित है, उनका चिन्हंकन कर मिशन मोड में पंजीयन कराया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अभियान के दौरान प्रत्येक तहसील में पात्र कृषकों की शत-प्रतिशत फार्मर आईडी बनाए जाने का कार्य सुनिश्चित किया जाए। फार्मर आईडी बनने से किसानों को कृषि संबंधी योजनाओं, उपार्जन, उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र एवं फसल बीमा सहित विभिन्न शासकीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। प्रशासन द्वारा किसानों से अभियान में सक्रिय रूप से सहभागिता कर अपनी फार्मर आईडी बनवाने तथा यदि आवश्यक हो तो अपनी भूमि एवं सर्वे नंबर से संबंधित जानकारी का सत्यापन कराने की अपील की गई है।

नर्मदापुरम में पिछले साल से 16.68 इंच कम बारिश हुई

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम जिले में इस बार मानसून की शुरुआत से ही बारिश का दौर कमजोर बना हुआ है। रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण अब तक 22.47 इंच पानी बरसा है, जो पिछले साल की तुलना में 16.68 इंच कम है। कम बारिश का असर तवा डैम पर भी दिखाई दे रहा है, जो फिलहाल 46 फीसदी ही भरा है। बारिश के करीब 40 दिन शेष हैं, ऐसे में डैम पूरी तरह नहीं भरने पर अगले साल गर्मी की मूंग फसल की सिंचाई के लिए नर्मदापुरम और हरदा के किसानों के सामने जल संकट खड़ा हो सकता है।

तवा डैम 1144 फीट पर, 54% खाली: सिंचाई विभाग के ईं अंकित सराफ के मुताबिक तवा डैम का जलस्तर 1144 फीट है और डैम 54 फीसदी खाली है। बैतूल और पचमढ़ी क्षेत्र से धीरे-धीरे पानी की आवक हो रही है। मौजूदा स्थिति को देखते



हुए डैम के 70 से 75 फीसदी तक भरने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि डैम 100 फीसदी नहीं भरा तो मूंग फसल की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना मुश्किल हो सकता है।

पचमढ़ी में सबसे ज्यादा, माखननगर में सबसे कम बारिश: जिले में ढाई माह में सबसे ज्यादा 844 मिमी बारिश पचमढ़ी में और सबसे कम 352 मिमी माखननगर में दर्ज हुई है। सिवनी मालवा में 539, इटारसी

में 572, सोहागपुर में 549, पिपरिया में 553.6, बनखेड़ी में 564.8 और डोलरिया में 481.3 मिमी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 21 और 22 अगस्त को बारिश की संभावना जताई है। हालांकि गुरुवार सुबह से मौसम साफ है और धूप खिली हुई है।

नर्मदा और प्रमुख बांधों का जलस्तर: सेठानी घाट: 938.9 फीट तवा बांध: 1144.0 फीट बरगी बांध: 1382.8 फीट बारना बांध: 1138.0 फीट ।

प्रतिबंध के बाद भी बन रहा था एनालॉग पनीर

सीहोर में डेयरी से 26 किंवटल जस्त पैकेट पर कंपनी नाम-लेबलिंग भी गलत मिली

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। सीहोर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए रुद्रांश डेयरी से 25 किंवटल एनालॉग पनीर जब्त किया है। यह कार्रवाई पचामा गांव स्थित डेयरी पर की गई, जहां एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार प्रतिबंधित पनीर पकड़ा गया है। प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है।

संभागीय उड़नदस्ता भोपाल और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सीहोर की संयुक्त टीम ने रुद्रांश फैक्ट्री पर छापा मारा। उड़नदस्ता प्रभारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि खाद्य आयुक्त को सीहोर में नकली एनालॉग पनीर बनाए जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

पैकेट पर लेबलिंग भी गलत थी: जांच के दौरान फैक्ट्री



में नमक और शक्कर मिली। संभागीय उड़नदस्ता प्रभारी ने बताया कि पनीर निर्माण में कई खामियां पाई गईं। पैकेट पर कंपनी और उत्पाद का नाम नहीं था, साथ ही लेबलिंग भी गलत थी। जब्त किए गए 25 किंवटल पनीर को सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, पचामा गांव स्थित रुद्रांश फैक्ट्री में लंबे समय से अमानक पनीर तैयार किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में 12 अगस्त को एनालॉग

पनीर पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी यहां इसका उत्पादन जारी था। इससे पहले भी, सूचना मिलने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सीहोर की टीम ने इसी फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 किंवटल से अधिक एनालॉग पनीर जब्त किया था। उस कार्रवाई के बावजूद फैक्ट्री में एनालॉग पनीर का निर्माण नहीं रुका और लगातार बड़ी मात्रा में अमानक पनीर बनाया जा रहा था।

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों

का प्राथमिकता से निराकरण, शिविरों में हुआ शत-प्रतिशत समाधान

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। आम नागरिकों की बिजली प्रदाय संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुपालन में मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में उपभोक्ताओं को विद्युत संबंधी समस्याएं एवं शिकायतें प्राप्त कर उनका त्वरित निराकरण किया गया। विभाग द्वारा शिविरों में प्राप्त समस्याओं के शत-प्रतिशत समाधान की पहल की गई है। शिविरों में नवीन विद्युत कनेक्शन, नीचे लटक रहे विद्युत केबल एवं तारों को व्यवस्थित करने, मीटर संबंधी शिकायतों, स्मार्ट मीटर लगवाने, बिजली बिल एवं विद्युत भार बढ़ाने सहित अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। विद्युत विभाग की टीम द्वारा अधिकांश शिकायतों का मौके पर अथवा उपभोक्ताओं के घर पहुंचकर त्वरित निराकरण किया गया। शिविर के दौरान श्री प्रयाग सिंह कुशवाहा ने घर में लगे विद्युत मीटर के तेज चलने तथा अधिक बिजली बिल आने की शिकायत दर्ज कराई। विद्युत विभाग की टीम ने शिकायत का मौके पर ही समाधान किया। इसी प्रकार कृष्णा कॉलोनी निवासी श्री सतीश चंद्र सक्सेना ने बिजली बिल का विद्युत भार बढ़ाने के लिए आवेदन दिया, जिसका विभागीय टीम द्वारा निराकरण कर दिया गया। श्री इरफान कुरैशी ने विद्युत मीटर लटकने की शिकायत की थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम उनके घर पहुंची और मीटर को व्यवस्थित कर दिया। कृष्णा कॉलोनी निवासी श्री जीएन शर्मा ने स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए आवेदन किया था। विद्युत विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके घर पहुंचकर स्मार्ट मीटर स्थापित किया। इसी तरह श्री कुलदीप मालवीय ने मीटर के नीचे लटक रही विद्युत केबल को व्यवस्थित करने के लिए आवेदन दिया। विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर विद्युत लाइन को ऊपर कर व्यवस्थित किया। वहीं श्री रघुवर प्रसाद पासी ने नवीन बिजली अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर लीए लगाने पड़ रहे हैं। विभाग द्वारा शिविरों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।
